मार्च 2020

₹ 20

समाजवादी बुलेटिन

समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक

कायाकल्प

20

कोरोना का आर्थिक कहर

6

खास बातचीत : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज

34

R.N.I. No. 68832/97

समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी। पार्टी में नौजवानों की बड़ी तादाद है और भविष्य में पार्टी इनके ही हाथों में होगी। परिवर्तन की राजनीति की समाजवादी पार्टी की परंपरा आगे भी जारी रहेगी। नौजवान समाजवादी सिद्धांतों व साहित्य को जरूर पढ़ें।

मुलायम सिंह यादव

संस्थापक-संरक्षक, समाजवादी पार्टी

समाजवादी बुलेटिन

मार्च 2020

वर्ष 21 | संख्या 6

प्रिय पाठकों,

समाजवादी बुलेटिन का यह नया अंक बदले हुए रंग-रूप और कलेवर में आपके हाथों में है। इसमें समाचार के साथ विचार का संतुलन बनाये रखते हुए आपके लिए पठनीय सामग्री को हर पन्ने पर समेटा गया है। हम निरंतर ऐसी ही सामग्री लेकर आयेंगे। आशा है आपको बुलेटिन का यह नया रूप पसंद आयेगा। आपकी प्रतिक्रिया की हमें प्रतीक्षा रहेगी।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक

प्रोफेसर रामगोपाल यादव

☎ 0522 - 2235454

samajwadibulletin19@gmail.com

bulletinsamajwadi@gmail.com

Mob:- 9598909095

/samajwadiparty

समाजवादी पार्टी के लिए

19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित

आस्था प्रिंटर्स, गोमती नगर, लखनऊ से मुद्रित

R.N.I. No. 68832/97

अंदर

खास बातचीत 34

"समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज

20 कवर स्टोरी

संकल्प 2022,लक्ष्य कायाकल्प

समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 14 मार्च 2020 को लखनऊ में हुई जिसमें देश व उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में बने अराजक माहौल से जनता को मुक्ति दिलाकर कायाकल्प का संकल्प लिया गया।

6 नजरिया

कोरोना का आर्थिक कहर

अभी तो नोटबंदी और जीएसटी की मार के साथ ही वैश्विक मंदी से अर्थव्यवस्था जूझ रही थी कि कोरोना ने एक और चोट की है।

किसानों को मिला सपा का साथ 38

यूपी का बजट 48 लोहिया जी की सप्त क्रांति 42

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

(11 फरवरी 1941 - 27 मार्च 2020)

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व केन्द्रीय मंत्री व राज्यसभा सदस्य श्री बेनी प्रसाद वर्मा 'बाबूजी' का 27 मार्च को लखनऊ में निधन हो गया। उन्होंने लखनऊ स्थित मेंदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली जहां उनका इलाज चल रहा था। वे 79 वर्ष के थे।

11 फरवरी 1941 को बाराबंकी जनपद के सिरौली ग्राम में उनका जन्म हुआ था। समाजवादी विचारधारा के प्रबल पैराकार श्री बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से प्रमुख थे। उन्होंने लोकसभा व उत्तर प्रदेश विधानसभा के कई बार सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। वे केन्द्र व राज्य सरकार में मंत्री रहे। वर्ष 2016 में वे समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। बीमार

होने व अस्पताल में भर्ती होने से पहले तक वे समाजवादी पार्टी को अपने बहुमूल्य परामर्शों से लाभान्वित करते रहे।

उनके निधन की सूचना मिलते ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव तत्काल अस्पताल पहुंचे एवं दिवंगत बेनी बाबू को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की व उनके शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि शोक की इस घड़ी में पूरा समाजवादी परिवार स्वर्गीय श्री वर्मा के परिजनों के साथ खड़ा है एवं हमेशा साथ रहेगा। श्री अखिलेश यादव ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे एवं उनका निधन पार्टी व समाजवादी आंदोलन के लिए अपूरणीय क्षति है।

बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी के संस्थापक और देश के दिग्गज नेताओं में शुमार किये जाते थे। बेनी बाबू सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी नेताओं में से थे। श्री वर्मा 1993 सरकार में प्रदेश के लोकनिर्माण और संसदीय कार्यमंत्री बने। वे 1996 में कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए व केन्द्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार में केन्द्रीय संचार मंत्री बनाए गए। उसके बाद वे 1998, 1999, 2004 में भी यानी लगातार चार बार कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। वे 2009 में गोण्डा से सांसद निर्वाचित होकर केन्द्रीय मंत्री बने। 2016 में बेनी बाबू राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए।

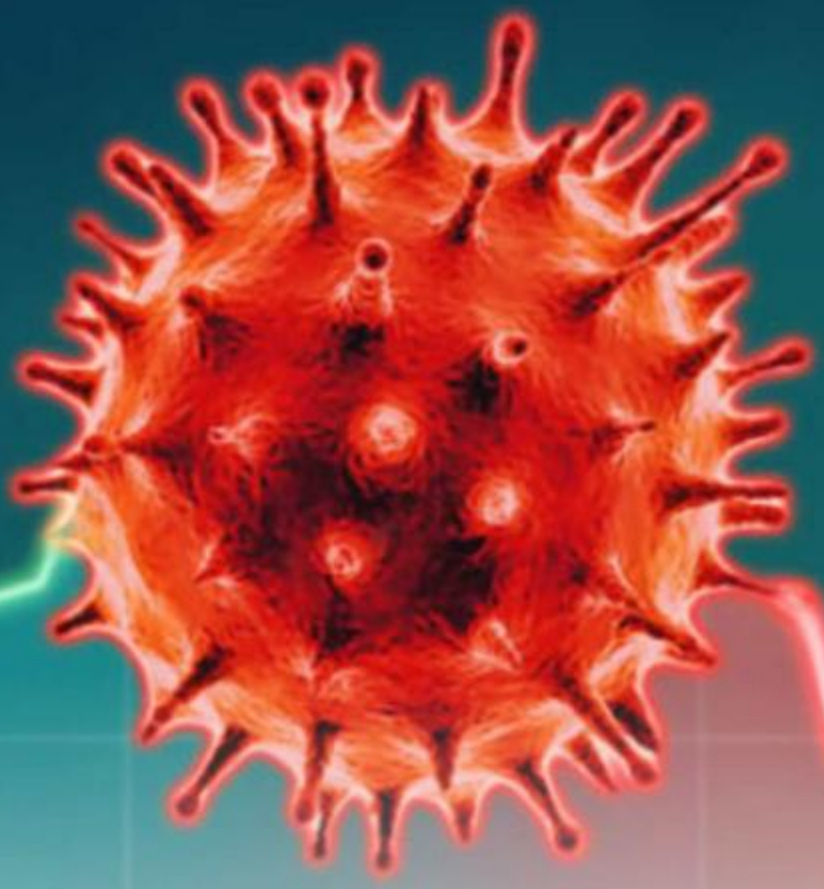

कोरोना का आर्थिक कहर

अरविन्द मोहन

वरिष्ठ पत्रकार, लेखक

कोरोना की वैश्विक उठापटक और आर्थिक मंदी की स्थिति में भविष्य के अनुमान सम्बन्धी आंकड़े देना जोखिम का काम है, पर जब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने समय से पूर्व रिजर्व बैंक की छमाही समीक्षा, मौद्रिक नीतियों में बड़े बदलाव और अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर कई घोषणाएं की तो आंकड़े सिरे से नदारद थे। यह पहली बार हुआ कि रिजर्व बैंक ने विकास दर जैसी प्राथमिक सूचना का अनुमान भी नहीं बताया जिसके बिना आगे की तस्वीर और फिर उस आधार पर लिए गए फ़ैसलों की समीक्षा की जा सके।

भारत की मौजूदा सरकार का आंकड़ों से डर और आंकड़ा जुटानेवाली व्यवस्था से छेड़छाड़ अब जगजाहिर है और इस क्रम में वित्त मंत्री बिना आंकड़ों के बजट तक पेश कर चुकी हैं, पर रिजर्व बैंक से यह उम्मीद किसी को न थी, लेकिन उसने आगे के लिए जो फैसले लिए उससे उसके ही अनुमान का अंदाजा हो जाता है। उसने रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट घटाने समेत काफी सारे ऐसे फैसले लिए जो दस साल से ज्यादा अवधि से नहीं हुए थे और आम तौर पर आनेवाले आर्थिक संकट के मद्देनजर उन्हें उपयोगी और जरूरी माना गया। रिजर्व बैंक की तरफ से कहा यही गया कि कोरोना महामारी लॉकआउट के मद्देनजर यह जल्दबाजी हुई और ऐसे फैसले भी हुए।

इससे एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कोरोना संकट के नाम से ही

एक बड़े आर्थिक पैकेज (करीब 1.70 लाख करोड़ रुपए) की घोषणा की और शेयर बाजार से लेकर आम आदमी तक ने राहत महसूस की कि सरकार को कुछ व्यावहारिक और जरूरी कदम उठाना भी आता है। वैसे तो यह पैकेज कोरोना के नाम से आया और मौजूदा स्थिति में इससे मदद भी मिलेगी पर असल में यह आर्थिक मंदी की शुरुआत मानने के बाद एक-सवा साल का चौथा या पांचवा पैकेज है। जो बात इसके बारे में कही जा सकती है वह पहले के पैकेजों को लेकर नहीं कही जा सकती। वे सबके सब उद्योगपतियों और व्यापारियों के हक वाले थे और सचमुच सरकार ने मुख्य रूप से लोगों का पैसा पूंजीपतियों की जेब में पहुंचाया। इस बार के पैकेज का ज्यादातर पैसा अर्थव्यवस्था के ज़रूरतमंद हिस्सों में जाएगा और इससे आर्थिक गतिविधियाँ बढेंगी जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। अभी तो नोटबंदी और जीएसटी की मार के साथ ही वैश्विक मंदी से अर्थव्यवस्था जूझ रही थी कि कोरोना ने एक और चोट की है। नोटबंदी तथा जीएसटी के फ़ैसलों की अपार असफलता और नुकसान से कुछ भी सबक न लेने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिना तैयारी और डेढ महीने देर से 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित करके अर्थव्यवस्था को इतनी बड़ी चोट पहुंचाई है कि उसका क्या होगा सहज कल्पना भी नहीं की जा सकती, कोरोना का जो होगा सो होगा।

भले ही रिजर्व बैंक कोई अनुमान न बताए पर दुनिया भर की संस्थाओंऔर अर्थशास्त्रियों के अनुमान आने शुरू हो गए हैं। विश्व प्रसिद्ध मूडीज ने भारत के जीडीपी में 2.5 फीसदी गिरावट की भविष्यवाणी की है। अगर हम इस साल अर्थव्यवस्था का विकास दर पांच फीसदी से नीचे जाने का अनुमान कर रहे हैं तो उसमें ढाई फीसदी गिरावट का क्या मतलब होगा? नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार का अनुमान है कि नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर शून्य या ऋणात्मक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिना तैयारी और डेढ महीने देर से 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित करके अर्थव्यवस्था को इतनी बड़ी चोट पहुंचाई है कि उसका क्या होगा सहज कल्पना भी नहीं की जा सकती

हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकानामिक कोआपरेशन ऐंड डेवलपमेंट का अनुमान है कि गिरावट दो फीसदी की होगी। अरुण कुमार जैसे अर्थशास्त्री तो पहले से सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के साथ जीडीपी की गणना में असंगठित क्षेत्र का हिसाब शामिल न होने की बात भी करते हैं। उनका तो पहले से कहना था कि हमारी अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में आ चुकी है। क्रेडिट स्विस का अनुमान है कि लॉकडाउन से, जिसने भारत के कुल उत्पादन के 37 फीसदी हिस्से को ठप्प किया है, 21 दिनों में जीडीपी का करीब चार फीसदी हो सकता है। वैसे इस बात पर आम सहमति सी है कि कोरोना रोकने के नाम पर उठाए कदमों से नौ लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा।

क्रेडिट स्विस के एशिया पैसेफिक इक्विटी स्ट्रेटेजी के प्रमुख नीलकंठ मिश्र का अनुमान है कि अभी काफी सारे संकेत हैं जो बताते हैं कि कोरोना वाला नुकसान और ज्यादा एवं लंबा पसर सकता है। एक तो लॉकडाउन 21 दिन में ही खत्म हो इसकी सम्भावना कम लग रही है। एक तो बीमारी का लक्षण ऐसा है और दूसरे सरकारी पैकेज का अधिकांश काम तीन महीने वाला ही है। संभव है कि यह क्रम कई तिमाही तक पैर पसारता जाए पर ज्यादा मुश्किल इस बात से आएगी कि विदेशी पूंजी का आना मुश्किल हो जाएगा जो पिछले साल भर से हमारी जरूरत का एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा हुआ करती थी। दुनिया की आर्थिक गतिविधियों में कमी आने का हमारे निर्यात पर असर होगा। वैसे भी हमारा वैश्विक व्यापार पिछले छह सालों से एक ही जगह रुका पड़ा है। हां, यह जरूर होगा कि तेल की कीमतें गिरने से हमें कुछ राहत होगी लेकिन जब आर्थिक गतिविधियां ही कम होंगी तो यह भी कितना लाभकारी होगा, कहना मुश्किल है। संभव है कि अमेरिका और यूरोप के देशों द्वारा अपनी-अपनी अर्थव्यवस्था को चढ़ाने के लिए घोषित कदमों से (अकेले अमेरिका ने 2.2 ट्रिलियन डालर का पैकेज घोषित किया है

जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था से जरा ही कम है) से बाजार में नई मांग आए और हमें भी उसका लाभ हो।

पर जो नुकसान, 'सबसे बलवान' मोदी महाराज के पिछले दो कदमों से हुआ है और इस लॉकडाउन से होता नजर आ रहा है वह स्थायी किस्म का है। ज्यादातर छोटे दुकानदार और कारोबारी स्थायी रूप से अपंग बने हैं और ऑनलाइन मार्केटिंग की क्या सीमा है और वह किस तरह हमारे बेरोजगार नौजवानों की बेचारगी पर निर्भर है यह लॉकडाउन ने दिखा दिया है। उसके भरोसे कितना व्यवसाय चलेगा यह कोई भी सोच सकता है। लाखों-करोड़ों लोगों का पलायन भी उपभोग और खपत की सामान्य प्रवृत्तियों को चौपट कर रहा है। उनके आय का नुकसान स्थायी है और किसी आर्थिक पैकेज भर से वापस पुरानी स्थिति में आ जाएगा यह संभव नहीं लगता, बल्कि इसमें हो यह रहा है कि चाहे प्रवासी मजदूर हों, स्वरोजगार वाले करोड़ों लोग या फिर पेंशन और बचत पर जीवन गुजारने वाले लोग, सभी अपनी बचत को ही निकालकर या उधार लेकर खा, पी रहे है। अर्थव्यवस्था के उत्पादक कामों में जाने की जगह बचत का यह इस्तेमाल आर्थिक रूप से नुकसानदेह है। प्रवासी मज़दूरों के पास न तो ऐसी बचत

होती है न उसे आसानी से उधार भी उपलब्ध होता है। इसीलिए वह अपने समाज की तरफ भागता है क्योंकि लाख मुश्किलों में भी समाज साथ देता है, सरकार या शासन नहीं।

इस संकट में पूरे निजी क्षेत्र की, खास तौर से स्वास्थ्य और शिक्षा के निजीकरण की सीमा भी दिखी, अगर कोई देखना चाहे तब। पर लॉकडाउन और कोरोना संकट ने अर्थव्यवस्था के और किन किन क्षेत्रों को चौपट किया है इसका हिसाब समझना मुश्किल नहीं है। पर्यटन, होटल और ट्रांसपोर्ट कारोबार वगैरह तो फिलहाल ठप्प ही हैं और इनके हाल फिलहाल सामान्य होने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। टेलीकाम, रियल एस्टेट और आटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों पर सबसे बुरी मार पड़ी है। एफएमसीजी अर्थात दैनिक उपभोग की वस्तुओं की खपत भी प्रभावित हुई है। मामला सिर्फ उपभोग, सुख चैन से रहने का नहीं है रोजगार का भी है और रियल एस्टेट सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है।

मोदी राज शुरू होने के बाद से ही यह क्षेत्र बदहाल रहा है पर इधर इसके घिसटकर चलने के लक्षण दिखने लगे थे। लॉकडाउन और कोरोना के शोर ने इसे एकदम चौपट कर दिया है और कितने समय में यहां सामान्य गतिविधियां शुरू होंगी यह अनुमान कोई नहीं लगा पा रहा है। आटोमोबाइल कम्पनियों से भी सिर्फ उत्पादन में कटौती की सूचना आ रही है। मोबाइल कम्पनियों की बदहाली जगजाहिर है पर उनके काम-काज और उनके यहां काम करने वालों के रोजगार से ज्यादा बड़ा खतरा यह है कि वे कॉल और डाटा महंगा करेंगी जिससे सारी संचार क्रांति चौपट हो जाएगी और हमारे-आपके लिए मोबाइल-मोबाइल का खेल भी मुश्किल हो जाएगा।

खपत में सबसे ज्यादा कमी ग्रामीण इलाकों से आ रही है जो एक और बीमारी के साथ ही पसरने की ओर भी इशारा कर रही है, पर ध्यान देने की बात है कि ऐसा कोरोना काल में ही नहीं हुआ है। यह क्रम पहले शुरू हो गया था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खास तौर पर खेती किसानी की सबसे ज्यादा दुर्गति हो रही है। मछली पालन और मुर्गीपालन जैसे धंधे तो एकदम चौपट हो गए हैं। फल, सब्जी की खेती वालों पर भी बुरी मार पड़ी है। बे मौसम बरसात ने खड़ी रबी फसल को कितना नुकसान पहुंचाया है इसका हिसाब लगने का होश आए इससे पहले कोरोना ने चोट की है और अब फसल

काटने और दाना निकालने वालों का अकाल हो गया है। यह पलायन की वजह से हुआ है, जो दिल्ली-मुम्बई जितने चर्चित ढंग से नहीं हुआ है। ठीक फसल तैयार होने के समय हुए लॉकडाउन से किसानों की और बुरी गत बना दी है। जिस तरह लॉकडाउन से भाग रहे मजदूरों को किसी तरह बस वगैरह देने की अक्ल आई उसी तरह सरकारों ने गन्ना पेराई सीजन के मद्देनजर चीनी मिलों को चालू रखने का फैसला किया।

ऐसे में सरकार और फिर रिजर्व बैंक की तरफ से हुई घोषणाओं की दिशा का सही होना कुछ उम्मीद जगाता है पर बार-बार यह बात साफ दिखती है कि ये अपर्याप्त हैं। इतने भर से अर्थव्यवस्था को जिलाए रखना, अर्थात पुरानी स्थिति में बचाना भी मुश्किल होगा। गिरावट और अर्थव्यवस्था का सिकुड़ना तो होगा ही, उसे रोकने के लिए ज्यादा बड़े पैकेज और मजबूत इरादों से काम करने की जरूरत है। बाकी दुनिया क्या कर रही है और महाशक्ति अमेरिका और चीन का कर रहे हैं, उस पर नजर डालने से भी हमारी तैयारियों की कमी जाहिर होगी। अमेरिका ने अपनी जीडीपी के दस फीसदी आकार का पैकेज घोषित किया है जबकि हमारा पैकेज एक फीसदी से कम (0.80 फीसदी) है। कम से कम चार पांच फीसदी आकार का पैकेज ही मौजूदा संकट को संभाल पाएगा। फिर खास-खास उद्योगों के लिए अलग-अलग तरह का इंतजाम करना होगा।

जो कुछ पिछले समय से सरकार की तरफ से हो रहा है उसका ज्यादातर हिस्सा निराश करने वाला ही है। पिछले दिनों खुद प्रधानमंत्री अपने नौकरशाहों को सार्वजनिक रूप से फटकार लगा रहे थे कि आपने मेरा पहला कार्यकाल नाश कर दिया, मैं दूसरे को नाश नहीं करने दूंगा। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर तो जैसे मोर्चा लगाकर ही बैठ गए हैं। एक पुराने मुख्य आर्थिक सलाहकार तो विकास दर के सरकारी अनुमान में ढाई फीसदी तक का खोट मानते हैं। यहां हम नए सूचकांक बनाने के समय करीब दो फीसदी का मार्जिन छोड़ने को

विदेशी पूंजी का आना मुश्किल हो जाएगा जो पिछले साल भर से हमारी जरूरत का एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा हुआ करती थी। दुनिया की आर्थिक गतिविधियों में कमी आने का हमारे निर्यात पर असर होगा।

लेकर हुई चर्चा को याद कर सकते हैं। बल्कि मोदी राज में सारे सरकारी आंकड़ों का संदिग्ध हो जाना ही सबसे बड़ी आर्थिक त्रासदी है। कहना न होगा कि नोटबन्दी में आंकड़े छुपाने की खुल्लमखुल्ला कोशिश (जिसके नायक तब के वित्त सचिव और आज के रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं) के पहले से ही यह अविश्वसनीयता जकड़ने लगी थी। मोदी जी और उनकी मंडली को लगता है कि राजनैतिक लुकाछुपी और बालाकोट जैसी चालाकी से चुनाव जीतने जैसे कारनामे हो सकते हैं तो आर्थिक आंकड़ों की लुकाछिपी क्यों नहीं हो सकती। पर इस चक्कर में हो यह रहा है कि अंग्रेजी हुकुमत और फिर नेहरू राज में महालोबनीस जैसे लोगों द्वारा पूरी स्वतंत्रता के साथ सांख्यिकी का जो जबरदस्त जाल बनाया गया था आज वह पूरी तरफ ध्वस्त हो गया है और सरकार खुद आंकड़े जुटाने को रोकने की पैरवी करने लगी है और मोदी राज में सामने आए सारे आंकड़े दुनिया की नजर में अविश्वसनीय बन गए हैं।

सरकार सच्चाई को स्वीकारने और एकमुश्त पैकेज देकर सबको काम पर लगाने की मुहिम छेड़ने की जगह बेमतलब दांवपेंच और अपने 'लोगों' को लाभ देने में लगी है। इन अपने लोगों की पहचान छुपी नहीं है। कुल कितने घरानों का कारोबार इस दौर में तेजी से बढ़ा है (वैसे पिछले शासन में भी ऐसे ही अधिकांश लोगों की सम्पत्ति तेजी से बढ़ी थी)। उसका हिसाब छिपा नहीं है। अडानी समूह सर्वाधिक प्रिय हो सकता है पर अंबानी बंधुओं की भी कम नहीं चल रही है। एक को जिस तरह से राफेल सौदे में लाभ दिये गए वे जगजाहिर हैं, वहीं दूसरे को फोन-इंटरनेट का सारा धंधा समर्पित किया जा रहा है। बीएसएनएल और एमटीएनएल का धंधा तो डूब ही गया है या डुबो दिया गया है, अब उसकी सारी बेशकीमती सम्पत्ति और इंटरनेट नेटवर्क को हड़पने की तैयारी है। सारी दूसरी निजी कम्पनियां भी जियो के आगे दम तोड़ रही हैं

और उनका घाटा डेढ़ लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। वोडाफोन प्रमुख ने काम छोड़ने तक की घोषणा कर दी थी तो उसका देसी पार्टनर बिड़ला भी हाथ खड़े कर चुका है। गिनती के लोग फल-फूल रहे हैं और मुश्किल यह है कि सरकार मंदी से लड़ने के नाम पर जो कदम उठा रही है वह ज्यादातर इन्हीं लोगों को लाभ दे रहा है। अच्छी बात यही है कि कोरोना की लडाई में जो कदम उठे हैं उनमें यह नहीँ दिखता, पर लगता है मोदी जी अपना समय खराब कर चुके हैं और नोटबन्दी तथा जीएसटी की तरह कोरोना/लॉकआउट के फैसले से मुल्क और अर्थव्यवस्था का जनाजा निकालने वाले हैं। भाई साहब, जब खुद अर्थव्यवस्था की समझ न हो तो कुछ जानकारों से पूछ सकते है। यह शर्म की बात नहीं है। सरकार ऐसे ही चलती है!

(यह लेखक के अपने विचार हैं।)

कोरोना की मुश्किल घड़ी में समाजवादियों ने बढ़ाए मदद के हाथ

कोरोना महामारी से उपजे हालात में समाजवादी पार्टी हमेशा की तरह अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का भरपूर निर्वहन कर रही है। पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष व संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव व सांसद जया बच्चन ने अपनी सांसद निधि से कोरोना राहत उपायों के लिए मदद की घोषणा की है, वहीं कई विधायकों ने भी अपनी-अपनी विधायक निधि से ऐसी ही मदद का ऐलान किया है।

इतना ही नहीं कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन के कारण खाद्य सामग्री की समस्या से जूझ रहे लोगों, खास कर गरीबों व दैनिक मजदूरों के लिए सपा के कार्यकर्ताओं ने हर जिले, हर ब्लाक, हर गांव में खाने-पीने की व्यवस्था की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के कार्यकर्ता लॉकडाउन के बाद से ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए इस काम में जुटे हैं।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी की वजह से देश में अचानक से लॉकडाउन लागू है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों एवं सड़कों पर लाखों लोग भूखे-प्यासे हैं। आपूर्ति संकट से जनता परेशान है। इन हालात में सत्तादल की जिम्मेदारी जहां ज्यादा है वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी जनता के दुःखदर्दो के प्रति पूर्णतयः संवेदनशील है और गरीबों, असहायों की मदद करने की पार्टी की परंपरा को पूरी शिद्दत से निभाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस निर्देश के मद्देनजर पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक तथा कार्यकर्ता दिन रात

अखिलेश जी ने सरकार को दिए अहम सुझाव

कोरोना महामारी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश को इस संकट से उबारने के लिए समाजवादी पार्टी निरंतर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव प्रदेश सरकार को सोशल मीडिया के जरिए लगातार अहम सुझाव दे रहे हैं।

एक अहम सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार से जनता में विश्वास जगाने वाले कदम उठाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय ले तो वह गांव-गांव तक फैले समाजवादी पार्टी के संगठन व कार्यकर्ताओं की साइकिल के माध्यम से खाद्य-दवा आदि के वितरण में मदद ले सकती है। खास तौर पर जो बच्चे मिड-डे मील में पौष्टिक आहार पा रहे थे, उनके लिए इस कोरोनाकाल में घरों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था सरकार तत्काल करे। समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार है।

श्री अखिलेश यादव ने फसल पकने के बाद खेतों में खड़ी फसल की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए कहा कि कोरोना लाॅकडाउन के चलते फसल काटने के लिए मुंहमांगी कीमत पर मजदूर नहीं मिल रहे हैं। किसान की दूसरी चिंता यह भी है कि इन हालात में वह अपनी फसल कहां बेचेगा? क्या आढ़तियों के हाथों उसे औने-पौने दाम पर लुटाने की मजबूरी होगी? श्री अखिलेश यादव ने कहा कि इससे पहले से ही नोटबंदी से परेशान किसान अब लाॅकडाउन में तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। उसके सामने जीवन-मरण की समस्या गम्भीर रूप ले लेगी। गन्ना किसानों के बकाये का तत्काल भुगतान करने की सरकार द्वारा व्यवस्था की जाये।

सक्रिय हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की अपील पर कोरोना से बचाव के लिए समाजवादी पार्टी के सांसदों, विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों में अपनी निधि से आर्थिक मदद दी है। सपा संरक्षक एवं मैनपुरी से लोकसभा सदस्य मुलायम सिंह यादव ने सांसद निधि से 25 लाख रुपए मैनपुरी प्रशासन को दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना से बचाव के लिए आजमगढ़ मेडिकल कालेज को सांसद निधि से एक करोड़ रुपए, राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने कन्नौज मेडिकल कालेज को सांसद निधि से एक करोड़ रुपए, राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने सांसद निधि से फिरोजाबाद और इटावा जिला प्रशासन को 50-50 लाख रुपए की धनराशि की संस्तुति की है।

इसी तरह से नेता विरोधी दल रामगोविंद चौधरी ने अपनी विधायक निधि से 20 लाख रुपया, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन ने अपनी विधायक निधि से अंबेडकर नगर जिले को तीस लाख रुपया देने, सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा विधायक सुभाष पासी ने कॉरोना से बचाव और सरकारी अस्पताल में वेंटीलेटर देने के लिए अपनी विधायक निधि से एक करोड़ रुपया देने की संस्तुति की है। विधायकों में कन्नौज से सपा एमएलसी पुष्पराज जैन पम्पी ने 60 लाख रुपए, करहल मैनपुरी से विधायक सोबरन सिंह ने 25 लाख रुपए, अम्बेडकरनगर सपा एमएलसी हीरालाल यादव 25 लाख रुपए, लखनऊ-उन्नाव से एमएलसी सुनील सिंह साजन ने 25 लाख, कन्नौज से विधायक अनिल दोहरे विधायक

ने 20 लाख, इलाहाबाद से एमएलसी बासुदेव यादव ने 15 लाख रुपए, मैनपुरी सदर से विधायक राजकुमार राजू ने 15 लाख रुपए, जलालपुर से सपा विधायक सुभाष राय 10 लाख रुपए, बाराबंकी से एमएलसी राजेश कुमार यादव ने 10 लाख, सुजीत कुमार सिंह ब्लॉक प्रमुख ने 10 लाख रुपए, लखीमपुर खीरी से सपा एमएलसी ने शशांक यादव एमएलसी 10 लाख रुपए, शाहगंज से विधायक शैलेंद्र यादव ललई ने 10 लाख रुपए, एमएलसी अरविंद यादव ने 10 लाख रुपए, मैनपुरी किशनी से विधायक ब्रजेश कठेरिया ने 10 लाख रुपए, आजमगढ़ अतरौलिया से सपा विधायक डॉ संग्राम सिंह ने 25 लाख रुपए, कानपुर से विधायक हाजी इरफान सोलंकी ने पांच लाख रुपए, सपा के महाराष्ट्र से विधायक अबू आसिम आाजमी ने 50 लाख रुपए, शाहजहांपुर से सपा एमएलसी अमित यादव ने 10 लाख रुपए, इलाहाबाद के सपा एमएलसी राम बृक्ष यादव ने ने 10 लाख, जौनपुर के मल्हनी से सपा विधायक पारस नाथ ने 15 लाख, बरेली से सपा एमएलसी संजय मिश्रा ने 5 लाख रुपए, इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव अंशुल ने 25 लाख रु पए, गाजीपुर के सपा विधायक डॉ वीरेंद्र यादव ने 10 लाख रुपए, सीतापुर महमूदाबाद के विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने 5 लाख रुपए, लखनऊ मोहनलालगंज से सपा विधायक अम्बरीश पुष्कर ने 10 लाख रुपए, आजमगढ़ के गोपालपुर से विधायक नफीस अहमद ने 10 लाख रुपए, कानपुर आर्यनगर से सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने 10 लाख रुपए, मछलीशहर से सपा विधायक जगदीश सोनकर ने 20 लाख रुपए, एमएलसी उदयवीर सिंह ने 20 लाख रुपए, एलएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने विधायक निधि से 10 लाख रुपए देने के लिए अपने-अपने मूल जिलों के मुख्य विकास अधिकरियों और जिला प्रशासन को पत्र लिखकर उनकी विधायक निधि से पैसा लेकर कोरोना की रोकथाम के लिए क्षेत्रों को सेनेटाइज कराने और साफ सफाई कराने का आग्रह किया है। ■■

संकल्प-सहयोग-समाजवाद

कोरोना न सिर्फ एक महामारी के रूप में आई है बल्कि यह मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी साबित हो रही है। समाजवादी पार्टी के सिपाही इस चुनौती का मुस्तैदी से मुकाबला करते हुए मानवता की सेवा में तन-मन-धन से जुटे हैं।

नो-एन्ट्री

राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की अपील पर सपा कार्यकर्ताओं ने हर जिले, हर ब्लाक, हर गांव में जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ा दिए हैं ताकि कोई भूखा न सो पाए।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
महमूदाबाद·सीतापुर

पंकज रस्तोगी

सफल

संकल्प 2022
लक्ष्य कायाकल्प

समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक

14 मार्च, 2020- लखनऊ

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीयकार्यकारिणी की बैठक दिनांक 14 मार्च 2020 को लखनऊ में हुई जिसमें देश व उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में बने अराजक माहौल से जनता को मुक्ति दिलाकर कायाकल्प का संकल्प लिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने की। बैठक में पारित राजनीतिक एवं आर्थिक में राष्ट्रीय कार्यसमिति ने आह्वान किया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के होने वाले 2022 के चुनावों में श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनने वाली समाजवादी सरकार को प्रचण्ड बहुमत प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ता पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जी-जान से जुट जायें। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरनमय नंदा, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव, राज्यसभा सदस्य जया बच्चन, रामजी लाल सुमन, इन्द्रजीत सरोज, जो एन्टोनी, राम पूजन पटेल समेत अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।

राजनैतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश करते हुए पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान को अपने अनुसार नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। देश में संविधान में शक्तियों का पृथक्करण धुंधला पड़ गया है। कार्यपालिका के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए गए हैं। सरकार ने न्यायपालिका का प्रभाव शून्य करने तथा विधायिका को अपंग करने का काम किया है। जो स्वतंत्र मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता था आज उसी ने बड़े पूंजीपतियों की मदद से लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। अब सरकार की सनक के सामने विधायिका और न्यायपालिका लाचार नजर आती है। मीडिया सरकारी तोता हो गया है। वह सरकार की कमियों को उजागर करने के बजाय सरकार की चापलूसी में जुटी रहती है।

बैठक में कहा गया कि देश में नौकरियों की आरक्षण नीति के आधार पर 85 प्रतिशत वाली आबादी को 50 प्रतिशत तक जबकि 15 प्रतिशत वाली आबादी को 50 प्रतिशत भागीदारी प्राप्त करने का हक

प्राप्त है जो सरासर सामाजिक अन्याय है। समाजवादी पार्टी एक लंबी अवधि से मांग कर रही है कि विभिन्न जातियों वाले देश में जनगणना के समय सभी जातियों की भी जनगणना कराई जाए ताकि वर्तमान असंतुलित आरक्षण प्रणाली समाप्त हो और जिसकी जितनी आबादी हो उसी अनुपात में हक और सम्मान मिल सके। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मांग की कि जनगणना में सभी जातियों की गणना कराई जाए और जिसकी जितनी आबादी हो उसी अनुपात में उसको भागीदारी दी जाए। केन्द्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना न कराने की स्थिति में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सामाजिक न्याय के सिद्धान्त की प्रतिबद्धता के आधार पर जातीय आनुपातिक हक और सम्मान की व्यवस्था लागू करेगी।

देश में जनगणना के समय सभी जातियों की भी जनगणना कराई जाए ताकि वर्तमान असंतुलित आरक्षण प्रणाली समाप्त हो और जिसकी जितनी आबादी हो उसी अनुपात में हक और सम्मान मिल सके।

राजनैतिक एवं आर्थिक प्रस्ताव

राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने भाजपा सरकार को सांप्रदायिक सरकार बताते हुए कहा कि यह सरकार सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों को छिन्न-भिन्न करने पर तुली हुई है तथा इसके लिये अन्याय एवं हिंसा का सहारा ले रही है। प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो जाने एवं मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत उनकी फसलों का क्रय मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना करने का झांसा देकर किसानों के साथ अन्याय किया गया है। वास्तविकता यह है कि धरातल पर उनके लिए कुछ नहीं हुआ परन्तु लगभग 6 वर्षों में किसानों की हालत बद से बद्तर होती गई है।

देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज एक बार पुनः बैठ रही है। आज से लगभग 28 वर्ष पहले लखनऊ में ही ऐतिहासिक बेगम हजरत महल पार्क में समाजवादी पार्टी का गठन और प्रथम सम्मेलन हुआ था। स्थापना सम्मेलन में जो पहला राजनैतिक और आर्थिक प्रस्ताव लाया गया था, उसकी कुछ बातें समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की दूरदर्शिता का स्पष्ट उदाहरण है। स्थापना सम्मेलन में पारित किये गये प्रस्ताव के पहले पैराग्राफ का एक अंश का उल्लेख करना न केवल प्रासंगिक है बल्कि हमारे संस्थापक नेताओं की दूरदर्शिता का परिचायक भी है। वह पैरा इस प्रकार है- 'आज आम भारतीय का आत्मबल टूट चुका है, वह निराश, उदास और कहीं क्रोध में है। सत्ता उसके लिये एक भयानक राक्षस की तरह है जो हर पल उसका शोषण करती जा रही है। गाँव वीरान हो रहे हैं, खेती और किसान उपेक्षित है, बेकारी सुरसा की तरह बढ़ रही है। जहाँ लूट ही लूट है। कौन कितना लूट सकता है इसकी होड़ है।'

आज स्थिति उससे बहुत ज्यादा बदतर हो चुकी है। देश की इस भयावह स्थिति को समझने के लिये हमें देश के वर्तमान राजनैतिक पटल पर दृष्टि डालनी होगी। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। वर्ष 2019 के आम चुनाव के परिणामों पर निगाह डालने के पश्चात कुछ सवाल सामने आये हैं जिन पर गहराई से विचार किये जाने की आवश्यकता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था की थी उसके हिसाब से संसदीय लोकतंत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये एक निश्चित व्यवस्था की गयी थी। जिसमें संसद और विधानमंडलों का काम कानून बनाने का, कार्यपालिका का काम कानून के पालन कराने का और न्यायपालिका का काम कानून की व्याख्या करने और कानून को तोड़ने वालों के लिये दण्ड सुनिश्चित करने का था। संविधान ने भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को समता एवं बराबरी के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर दिया। लेकिन वह व्यवस्था एकदम बदल गयी। संविधान में वर्णित शक्तियों का पृथक्करण धुंधला पड़ गया है। कार्यपालिका ने लगभग सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिये हैं। न्यायपालिका को

विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने और उनकी खिलाफत करने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का प्रयोग करना भारतीय राजनीति के लिये सबसे अशुभ संकेत है।

प्रभाव शून्य करने तथा विधायिका को अपंग करने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। जो स्वतंत्र मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता था और जिसे लोकतंत्र का चैथा स्तम्भ माना जाता था उसका बड़े पूँजीपतियों की मदद से पूरी तरह से गला घोंट दिया गया है। अब सरकार की सनक के सामने विधायिका और न्यायपालिका लाचार नजर आती है। मीडिया सरकारी तोता हो गया है और वह सरकार की कमियों को उजागर करने के बजाय सरकार की चापलूसी करने में जुटी रहती है।

देश की मौजूदा सरकार का लक्ष्य केवल किसी न किसी तरीके से सत्ता में बने रहना और सत्ता को हासिल करना है। छल और बल से अपनी विचारधारा को जनता पर थोपना और जनता के सरोकार के सारे कार्यों की उपेक्षा करना एक सामान्य बात हो गयी है। आम जनता में यह धारणा है कि मौजूदा सरकार सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके देश को रक्तरंजित करके अपने सहयोगी संगठनों द्वारा प्रचारित और प्रसारित विचारधारा को ही अपना मार्गदर्शक मान कर काम कर रही है। संसद, सरकार एवं न्यायपालिका की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग व्यापक समाज एवं देश के लिये न करके सांप्रदायिक शक्तियों को मजबूत करने के लिये किया जा रहा है। इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यमों का प्रयोग करते हुए भारत वर्ष में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सहारा लिया गया है तथा भारतवर्ष में भय, असुरक्षा एवं नफरत का माहौल बनाकर समाज को बाँट दिया गया है। यह भी पूरी स्पष्टता के साथ परिलक्षित हो रहा है कि वर्तमान सरकार ब्रिटेन की उपनिवेशी सरकार की भाँति फूट डालो और शासन करो की नीति पर चल रही है।

वर्ष 2019 के आम चुनावों में सांप्रदायिक शक्तियों ने 36 प्रतिशत मत प्राप्त करके अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। यह बड़ी चिंता एवं विचार का विषय है कि पूर्ण बहुमत की सरकार भी जनता को सशक्त करके देश को आगे बढ़ाने की बजाय देशवासियों को ही लाचार एवं मजबूर बनाकर अपनी ताकत बढ़ाने में लग गई है।

आजादी के 70 वर्षों में जो भी पूर्ववर्ती सरकारें बनीं हैं, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से देशवासियों का विकास करने के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं बुनियादी निर्माण पर बल देने का काम किया था, परन्तु वर्तमान सरकार ने सिर्फ पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रति युद्ध का उन्मादी स्थाई माहौल बनाकर जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुँह मोड़ने का काम किया है।

सरकार एवं उसके सहयोगी संगठन एक तरफ राष्ट्रवाद की नई परिभाषाएं गढ़ रहे हैं तथा निर्लज्जतापूर्वक संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढाँचे को तहस-नहस करने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ गौरक्षा के नाम

पर पूरे देश में उन्मादी भीड़ द्वारा पीट-पीट कर सैकड़ों लोगों की हत्याएं की गयीं हैं तथा पुलिस एवं प्रशासन सिर्फ खड़े होकर देखते रहे हैं। स्वतंत्र भारत में घटने वाली ये घटनाएं देश के माथे पर कलंक के समान हैं तथा पूरे विश्व में इन घटनाओं के कारण देश की साख को नुकसान पहुँचा है। सरकार ने न सिर्फ दोषियों को बचाने का काम किया है वरन् अपना कर्तव्य निभाने वाले सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हतोत्साहित करने एवं दंडित करने का काम भी किया है। बिकाऊ पत्रकारिता के माध्यम से एक अनुकूल माहौल बनाकर सरकार अपने गुनाहों पर पर्दा डालने का काम कर रही है।

जनपद बुलन्दशहर में सांप्रदायिक एवं उन्मादी भीड़ द्वारा की गयी पुलिस निरीक्षक की हत्या तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों का जल्दबाजी में किया गया स्थानान्तरण एक ऐसा उदाहरण है जो अत्यंत निंदनीय है जबकि अधिकारियों द्वारा उचित कदम उठाकर एक बड़ा दंगा रोक दिया गया था, जिसके लिये उन्हें प्रशस्ति पत्र मिलना चाहिये था। परन्तु कातिलों को तत्काल जमानतें मिल जाना तथा उनका जेल से बाहर आने पर भव्य स्वागत किया जाना, एक ऐसा घटनाक्रम है जिसे याद रखा जाना चाहिये। चार राज्यों मेंे चुनाव होने जा रहे थे और ऐसे समय पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की योजना बनाई गयी थी ताकि इन राज्यों में चुनाव जीता जा सके।

गैर भाजपा शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाना और उन्हें गिराने का प्रयास करना भाजपा सरकार के लिये आम बात हो गयी है। विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने और उनकी खिलाफत करने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का प्रयोग करना भारतीय राजनीति के लिये सबसे अशुभ संकेत है। जो व्यक्ति इस सरकार की खिलाफत करे, वह देशद्रोही घोषित हो जाता है। वोट की खातिर दंगे कराना, असंवैधानिक कानूनों का बनाना भारत की एकता और अखंडता के लिये खतरे की घंटी के समान है। नागरिकता संशोधन अधिनियम, एनआरसी और एनपीआर की वजह से पूरे देश में बेचैनी है। सरकार की इन गतिविधियों से पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है।

जो प्रशासनिक विफलताएं सरकार के माथे पर कलंक का टीका लगा रहीं थीं उन्हीं को हथियार बनाकर सार्वजनिक संस्थानों एवं निगमों को निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है।

जब दिल्ली में चुनाव से पूर्व दंगा कराने में असफल रहे और चनुाव हार गये तो जो कुछ दिल्ली में हुआ, वह गुजरात के दंगों की याद दिलाता है। दिल्ली में दंगा के लिये उकसाने वालों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज ने एफआईआर करने के आदेश दिये तो उनका आधी रात्रि को तबादला कर दिया गया। न्यायपालिका पर इस तर ह का दबाब बनाकर ही उसे डराने-धमकाने की कार्यवाही वर्षों से चल रही है। संविधान द्वारा दिये गये समता, जीवन की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के चलते कोई भी नागरिक न्यायपालिका की मदद से सरकार से लड़ सकता है किन्तु अगर न्यायपालिका ही सरकार के दबाब में आ जाये तो न नागरिक स्वतंत्रता सुरक्षित है और न मौलिक अधिकार।

भारतवर्ष में लगभग 7200 जातियां तथा दस मज़हबों के लोग एक लम्बे समय से मिल-जुल कर रहते रहे हैं। ऐतिहासिक विरासत तथा स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई सभी देशवासियों की साझी विरासत है। संविधान के माध्यम से ऊँच-नीच की भावना को मिटाकर समता के आधार पर अवसरों की रचना के सिद्धांत ने भारतीय जनमानस को जीवन का एक नया आधार प्रदान किया है। समाज के निचले पायदान पर रहने वाले करोड़ों उपेक्षित लोगों के जीवन में प्रकाश की किरण आयी, जब उन्हें शिक्षा प्राप्त करके सरकारी नौकरियों में पर्याप्त अवसर मिले। इसके लिये संविधान में वंचित समुदायों के लिये आरक्षण का प्राविधान रखा गया था। इस भगवा हुकुमत को भारत के अल्पसंख्यक समुदाय का अपनी मेहनत से आगे बढ़ना अखर रहा था। उन्हें वंचित समुदायों का शिक्षित होना तथा बड़े पदों पर पहुँचना भी अखरने लगा। सरकारी नौकरियों में दलितों एवं पिछड़ों को मिलने वाला संवैधानिक आरक्षण कोटा पूरा करने की बजाय नीतियां तोड़-मरोड़ कर नौकरियां समाप्त करने का कुचक्र भी चालू हो गया है।

जो प्रशासनिक विफलताएं सरकार के माथे पर कलंक का टीका लगा रहीं थीं उन्हीं को हथियार बनाकर सार्वजनिक संस्थानों एवं निगमों को निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बहुत से सरकारी निगम जिनमें भारत की जनता का पैसा लगा था, उन्हें निजी क्षेत्रों को सौंप दिया गया है जिसके कारण बहुत से लोग नौकरियों से बाहर हो गये हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था न होने के कारण समाज के अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग के तबकों के करोड़ों युवाओं के जीवन में अंधेरा छा गया है। सरकारी नौकरियों में जहाँ 27 प्रतिशत पिछड़ों के लिये और 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के लिये नौकरियां आरक्षित हैं उन्हें भी एक तरह से खत्म कर दिया गया क्योंकि अब भर्तियों का काम आउटसोर्सिंग से होने लगा, जिस पर आरक्षण का कानून लागू नहीं होता है और जहाँ आयोगों से नियुक्तियां होती भी हैं वहाँ 85 प्रतिशत पिछड़े और दलित वर्ग के अभ्यर्थियों को 49.5 प्रतिशत और 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 50.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर दी गयी है। यह सरासर भारतीय संविधान की मंशा के खिलाफ है और देश की बहुसंख्यक जनता के खिलाफ गहरी साजिश है। इस पर राष्ट्रीय स्तर पर गम्भीरता से विचार करने और प्रभावित लोगों को संगठित करके आन्दोलन चलाने की आवश्यकता है।

देश में नौकरियों की आरक्षण नीति के आधार पर 85 प्रतिशत वाली आबादी को 50 प्रतिशत तक जब कि 15 प्रतिशत वाली आबादी को 50 प्रतिशत भागीदारी प्राप्त करने का हक प्राप्त है जो सरासर सामाजिक अन्याय है। समाजवादी पार्टी एक लम्बी अवधि से मांग कर रही है कि विभिन्न जातियों वाले देश में जनगणना के समय सभी जातियों की भी जनगणना कराई जाय ताकि वर्तमान असंतुलित आरक्षण प्रणाली समाप्त हो और जिसकी जितनी आबादी हो उसी अनुपात में हक और सम्मान मिल सके। भारत सरकार जनगणना का कार्य प्रारम्भ कराने जा रही है परन्तु जनगणना हेतु प्रत्येक परिवार से जनगणना के आंकड़े एकत्र करने हेतु

निर्धारित प्रारूप में सभी जातियों की जानकारी प्राप्त करने का कॉलम नहीं है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मांग है कि प्रारम्भ की जा रही जनगणना में सभी जातियों की गणना कराई जाए और जिसकी जितनी आबादी हो उसी अनुपात में उसको भागीदारी दी जाए।

केन्द्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना न कराने की स्थिति में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सामाजिक न्याय के सिद्धान्त की प्रतिबद्धता के आधार पर जातीय अनुपातिक हक और सम्मान की व्यवस्था लागू करेगी।

भारतवर्ष की 130 करोड़ की आबादी जिसका लगभग 80 प्रतिशत किसान, मजदूर, महिलाएं तथा अन्य श्रमशील जातियां हैं, जिन्होंने अपने हाथों से मेहनत करके धन एवं वैभव का निर्माण किया है। वे लाचारी एवं मजबूरी का जीवन जीने के लिये विवश हैं। यह सांप्रदायिक सरकार उनके सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों को छिन्न-भिन्न करने पर तुली हुयी है तथा इसके लिये अन्याय एवं हिंसा का सहारा ले रही है। प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2014 से किसानों की आमदनी 2022 तक दुगुनी हो जाने एवं मूल्य समर्थन योजना के अन्र्तगत उनकी फसलों का क्रय मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना करने का झांसा देकर किसानों के साथ घोर अन्याय किया गया है। वास्तविकता यह है कि धरातल में उनके लिए कुछ नहीं हुआ परन्तु लगभग 6 वर्षों में किसानों की हालत बद से बद्तर होती गई है।

ये कोई हैरत वाली बात नहीं थी कि जो सरकार राष्ट्रवाद का शंखनाद करते हुए जनता द्वारा चुनकर आयी थी, उसने जनता को कमजोर और लाचार बनाने के लिये बड़े अजीब और बेतुके निर्णय लेने चालू किये, उसमें नोटबन्दी का निर्णय सबसे महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री आश्चर्यजनक तरीके से टीवी पर आये और नोटबन्दी की घोषणा की, जिसके द्वारा उस समय प्रचलित 500 रूपये और 1000 रूपये के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था तथा उन्हें बदलने की समय सीमा तय कर दी गयी। पूरा देश अपना काम छोड़कर नोट बदलने के काम में लग गया। यह बताया गया था कि इस कदम से काला धन प्रकाश में आ सकेगा तथा आतंकी फंडिग में रोक लग सकेगी एवं नकली मुद्रा का प्रचलन बंद किया जा सकेगा। बाद में पूरे देश ने देखा कि लगभग पूरी की पूरी प्रचलित मुद्रा रिजर्व बैंक में आ गई। परन्तु जिन कारणों का जिक्र

प्रधानमंत्री ने किया था, वे कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके। वरन् पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में फँस गयी। यहाँ यह गौरतलब है कि प्रधानमंत्री द्वारा लिये गये इस दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय की जानकारी न तो रिजर्व बैंक को थी, न ही वित्त मंत्रालय को, न ही सरकार को और न ही संसद एवं मीडिया को हुई। पूरा बिकाऊ मीडिया प्रधानमंत्री की भाषा बोलता रहा। यहाँ तक कि बैंकों की लाइन में लगे लोगों की दुर्दशा और इस कारण से हुई मौतों पर भी देश का ध्यान नहीं गया। नोट बंदी के दौरान बैंकों की लाइन जिस तरह की असुविधा एवं परेशानी से पुरूषों और महिलाओं को गुजरना पड़ा वह लोकतांत्रिक सरकार के लिए शर्मनाक है, अनेकों पीड़ादायक घटनाओं में खजांची का जन्म कानपुर देहात के बैंक की लाइन में हुआ था।

भारत में बेरोजगारी चरम सीमा को पार कर गयी है। देश की जनता को गुमराह करने के लिये यह बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दिया गया है लेकिन निर्माण कार्यों में ठेकेदारों के नीचे काम कर रहे मजदूर और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर पूरी तरह से अस्थायी होते हैं। कोई एक महीने काम करता है, कोई दो महीने, कोई छह महीने। उनका प्रॉवीडेन्ट फण्ड काटकर उन्हें कर्मचारी दिखाकर रोजगार पाने वालों की संख्या में जोड़ दिया जाता है। अब तो सरकार भी आउटसोर्सिंग के जरिये कम्पनियों के माध्यम से अस्थायी भर्तियां करने लगी है। इस प्रकार जो सरकारी नौकरियां पाने वाले युवा थे, उनके लिये रोजगार के दरवाजे लगभग पूरी तरह बंद हो गये हैं। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है।

किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और परम कर्तव्य देश की सीमाओं की सुरक्षा का होता है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश की सीमाएं सिकुड़ रहीं हैं। आजादी के समय 1947 में हमारे देश का जितना क्षेत्रफल था उसमें लाखों वर्ग किलोमीटर की कमी आ गयी है। चीन और पाकिस्तान के कब्जे में भारत का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है लेकिन भारत सरकार उसे वापस लेने के लिये कोई प्रयास नहीं कर रही है।

हमारी विदेश नीति अपने मूल लक्ष्य से भटक गयी है। रूस हमारा सबसे विश्वसनीय मित्र देश था, लेकिन हमारी गलत नीतियों के चलते उसका झुकाव भी पाकिस्तान की तरफ होने लगा है। हमारे सभी पड़ोसी देशों से सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। उन सब पर चीन का प्रभाव है। इसलिये दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन पूरी तरह से चीन के पक्ष में हो गया है। हम बिना किसी संकोच के यह कह सकते हैं कि हमारे मित्र देशों की संख्या कम हुई है और शत्रु देशों की संख्या बढ़ी है जबकि सफल विदेश नीति वह होती है जिसमे मित्र देशों की संख्या बढ़े और शत्रु देशों की संख्या घटे।

भारत में बेरोजगारी चरम सीमा को पार कर गयी है। देश की जनता को गुमराह करने के लिये यह बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दिया गया है

भारतवर्ष में कृषि कार्यों पर आयकर नहीं लगता है परन्तु नोट बदलने के क्रम में किसानों, मजदूरों एवं गृहणियों को भी नहीं बख्शा गया। जिनके फलस्वरूप भारत की एक बड़ी श्रमशील आबादी का हाथ खाली हो गया तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली आर्थिक क्रियाएं मंद पड़ गयीं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पूँजी का निर्माण करने की गति ठहर गयी। विमुद्रीकरण के इस आघात ने अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण घटक "मांग" को प्रभावित किया और उसके फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन तथा निवेश भी गिरने लगा। इसके साथ ही पूरी बैंकिंग प्रणाली लड़खड़ा गई। बैंकों का एनपीए 18 प्रतिशत तक पहुँच गया। कई बैंकों को आपस में विलय करना पड़ा तथा जनता की गाढ़ी मेहनत की कमाई जो बैंकों में रखी थी वह अनिश्चितता एवं असुरक्षा की शिकार हो गई। केन्द्र सरकार के गलत निर्णय से नोट बंदी और जीएसटी के कारण यस बैंक डूब गयी, अन्य बैंकों के भी डूबने का संकेत है। यह स्थिति है कि भारत सरकार दुविधा में पड़ी है और इस मंदी से बाहर आने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। रिजर्व बैंक में कुछ भी रिजर्व नहीं है। सोना पहले ही गिरवी रख

दिया था। अब एक लाख पचहत्तर हजार करोड़ रुपया भी निकाल लिया है। सरकार के राजस्व लक्ष्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सामने अंधेरा है तथा सरकार जनता को भरमाने के लिये हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिकता का कार्ड खेलने में लगी है। बैंकिंग सिस्टम फेल होने की स्थिति में है।

यह गौरतलब है कि समुचित व्यवस्था होते हुए भी अर्थव्यवस्था का व्यवस्थित विनाश कैसे संभव हुआ और यह किस उद्देश्य से प्रेरित है। यह बड़ी चिंता का विषय है। इन्हीं प्रधानसेवक द्वारा चुनाव के पहले विदेशों में जमा काला धन वापस लाने के दावे किये गये तथा प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 15 लाख रुपए खातों में दिये जाने की झाँसे वाली कहानी को जिस तरीके से पीत पत्रकारिता के माध्यम से दबा दिया गया, यह अत्यंत रोचक विषय है जिस पर विशेष चिंता किये जाने की आवश्यकता है। सरकार एक जीवंत प्रक्रिया है जो पारदर्शी तरीके से काम करती है तथा ज्यादातर निर्णय जनहित में आम सहमति से लिये जाते हैं। परन्तु अब यह स्पष्ट हो रहा है कि पूरी सरकार तथा उसके नियामक तंत्र एक कठपुतली की भाँति कार्य कर रहे हैं। भारत की समुची लोकतांत्रिक प्रणाली एक कठिन दौर से गुजर रही है जहाँ सवाल पूछने वालों को देशद्रोही करार दिया जा रहा है और मीडिया इन लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर माहौल बना रहा है और सच्चाई के मार्ग पर चलने वालों पर प्राणघातक हमले किये जा रहे हैं।

सरकार विशेष तौर पर उन बुद्धिजीवियों को निशाने पर रखे हुए है जो सरकार से सवाल करते हैं तथा सरकार उनके सवालों से असहज महसूस करती है। सरकारी तंत्र जो कि भ्रष्ट हो रहा है ने कई विश्वविद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों एवं कलाकारों को 'शहरी नक्सलवादी' का दर्जा दिया और जेल में डालने का कार्य किया। क्योंकि ये लोग सरकार की मंशा को जनता के बीच उजागर करने का कार्य कर रहे थे। सरकार द्वारा संसद में "Unlawful Activities" एक्ट जल्दीबाजी में पास कराया गया जिससे कि स्वयं के विरोध को दबाया जा सके और सत्ता निरंकुश होकर देश को बदलने का कार्य कर सके।

सरकार की गलत नीतियों के कारण जो दुष्प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़े, उससे व्यापारियों तथा उद्योगपतियों का चैकन्ना होना स्वाभाविक भी था। अंतर्राष्ट्रीय संस्था Oxfam द्वारा अवगत कराया गया है भारतवर्ष में गरीब एवं अमीर लोगों के बीच की खाई खतरनाक हद तक बढ़ गयी है। मात्र नौ परिवारों के पास देश की 50 प्रतिशत पूँजी सिमट गयी है तथा 1 प्रतिशत आबादी के पास 73 प्रतिशत पूँजी तथा सम्पत्ति जा चुकी है। इसके दूरगामी परिणाम शीघ्र ही सामने आयेंगे। सरकार की अनुकम्पा पर जीने वाले कई नामचीन उद्योगपति राष्ट्रीयकृत बैंकों की हजारों करोड़ की पूँजी लेकर विदेश भाग चुके हैं। उन्हें कानूनी कार्यवाही करके वापस लाने में सरकार लाचार दिखाई पड़ रही है। परन्तु कई प्रतिष्ठित पूँजीपतियों द्वारा सरकारी निर्णयों और प्रक्रियाओं पर सवाल सार्वजनिक किये जाने पर आयकर विभाग तथा ईडी द्वारा विशेष छापे मारे गये ताकि

विरोध के स्वर दबाये जा सकें। इसका भी दुष्परिणाम यह हुआ कि हजारों की तादाद में उद्योगपति तथा विद्वान देश छोड़कर एनआरआई बन गये हैं और उन्होंने पूँजी निवेश देश के बाहर कर दिये हैं।

इस बदलते हुए भारत की दशा क्या है और क्यों है? आज यह सवाल सबके मन में जाना चाहिये। देश की आबादी लगभग 130 करोड़ पहुँच चुकी है। इसमें लगभग 85 प्रतिशत युवा हैं जो कि देश का भविष्य हैं। ये ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं तथा सभी जातियों, वर्गों एवं समुदायों से हैं। इनका भविष्य सुनिश्चित करना देश का कर्तव्य है। ये स्वस्थ हों, शिक्षित हों, चरित्रवान हों, हुनरमन्द हों, आत्मनिर्भर बनें तथा देश को आगे बढ़ायें। इन परिस्थितियों पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये। धार्मिक उन्माद, छल, प्रपंच, तिकड़म और झूठ के सहारे बनी हुई इस सरकार ने नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्हें एक बेहतर मानव संसाधन बनाने की बजाय उन्हें विभाजित करने का और आपस में लड़ाने का कार्य किया है और हताशा के गर्त में डुबाने का काम किया है। सरकार स्वयं भी अर्थव्यवस्था को डुबोने में लगी हुई है। यही मानव संसाधन देश को लाचारी एवं ऋणग्रस्तता से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। परन्तु यह सरकार की प्राथमिकता से बाहर है। विदेशी कर्जदारों के दबाब में सरकारी नीतियां बदली जा रहीं हैं और Ease of doing bussiness के दबाब में भारत की श्रमशक्ति को, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाचार और असुरक्षित किया जा

हमारी विदेश नीति अपने मूल लक्ष्य से भटक गयी है। रूस हमारा सबसे विश्वसनीय मित्र देश था, लेकिन हमारी गलत नीतियों के चलते उसका झुकाव भी पाकिस्तान की तरफ होने लगा है। हमारे सभी पड़ोसी देशों से सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। उन सब पर चीन का प्रभाव है।

रहा है। सारे श्रम कानूनों को इस तरह से बदला जा रहा है कि श्रम शोषण आसानी से किया जा सके। तथा उनकी मदद में खड़ी होने वाले श्रम संगठनों तथा राजनीतिक पार्टियों को कमजोर करने के लिये उपक्रम किये जा रहे हैं। इसके लिये पीत पत्रकारिता, भ्रष्ट नौकरशाही, भ्रष्ट पूँजीपति तथा अनौचित्यपूर्ण कानूनों इत्यादि हर चीज का सहारा लिया जा रहा है। जो महिलाएं आगे बढ़कर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहीं हैं उन्हें अच्छा माहौल नहीं मिल पा रहा है। महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध रिकार्ड तोड़ रहे हैं तथा उन्हें हतोत्साहित करने के लिये सरकारी संरक्षण में पलने वाले भगवाधारियों द्वारा भाँति-भाँति के बेतुके बयान दिये जा रहे हैं। जो सरकार बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नाटक बड़े पैमाने पर कर रही है वह इन पाखण्डियों पर कोई लगाम नहीं लगा रही है।

भारत सरकार का बजटीय आवंटन भी गौरतलब है। समाज के लगभग 90 प्रतिशत संघर्षशील दलित, पिछड़े तथा आदिवासियों के लिये कुल बजट में सिर्फ 4.73 प्रतिशत समर्पित बजट का प्रावधान किया गया है तथा 10 प्रतिशत लोग जो सक्षम हैं उनके लिये 95.28 प्रतिशत बजटीय प्रावधान रखे गये हैं। कई उपक्रम बन्द हो रहे है, नौकरियां समाप्त हो रहीं हैं। शिक्षा पर तथा स्वास्थ्य पर बजट कम किया जा रहा हैं। बेरोजगारी चरम पर है अब तो सरकार ने आँकड़ा रखना भी छोड़ दिया है। इन परिस्थितियों को बहुत गौर से देखकर विचार करने की जरूरत है।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जब खराब होती है तो स्वाभाविक रूप से गरीबी अपना आकार बढ़ाने लगती है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि ग्लोबल हंगर इन्डेक्स में कुल 117 देशों में भारत 102वें नम्बर पर है। खाद्यान्न के मामले में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता 1961 से भी खराब हो गयी है । स्मरण रहे कि 1960-61 में देश में भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गयी थी। उस वर्ष भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार चावल की उपलब्धता 73.4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, अन्य अनाज 43.6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष और दालें 25.2 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्ध थीं, जबकि 2017 में यह उपलब्धता चावल की 66.8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, अन्य अनाजों की 29.4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष और दालें 20 किलोग्राम

प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्ध थी। अर्थात् 1961 की तुलना में 2017 में चावल, मोटा अनाज और दालों की उपलब्धता कम हो गयी है।

बिजली की खपत प्रति व्यक्ति जिस देश में ज्यादा होती है वह देश उतना ही ज्यादा सम्पन्न होता है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बिजली की खपत 12962 किलोवाट ऑवर, कोरिया में 10556 किलोवाट ऑवर, आस्ट्रेलिया में 10002 किलोवाट ऑवर, जर्मनी में 7035 किलोवाट ऑवर, रूस में 6603 किलोवाट ऑवर, चीन में 3927 किलोवाट ऑवर और भारत में 1010 किलोवाट ऑवर है। एक तरफ भारत सरकार दुनिया की पाँच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में होने का दम भरती है वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में

खाद्यान्न की उपलब्धता और बिजली की खपत यह दर्शाती है कि हम दुनिया के छोटे-छोटे देशों की अर्थव्यवस्था से भी पीछे हैं। जहाँ तक आयात और निर्यात का प्रश्न है। 2014 से लेकर अब तक भारत का ट्रेड बैलेंस लगातार निगेटिव है। 2014-15 में

यूपी की भाजपा सरकार यानी नफरत की राजनीति

राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश के विषय में कुछ चर्चा आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार के तीन वर्ष पूर्ण हो रहे है परन्तु इस बीच प्रदेश की सरकार केवल समाज में नफरत की राजनीति करती रही। समाज में जातियों को तोड़ने तथा चुस्त प्रशासन के नाम पर पुलिस के माध्यम से भय एवं दहशत का वातावरण पैदा किया है। प्रदेश की विज़न एवं दिशाहीन भाजपा सरकार प्रदेश की जनता की समस्याओं एवं उनके दुख दर्द को बांटने में विफल रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जो उच्चकोटि के जनहित के विकास कार्य हुये थे उनके नाम बदलकर जनता को धोखा देने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश की जनता को त्वरित सुरक्षा प्रदान करने वाली यूपी डायल 100 सेवा को ही 112 नम्बर में बदलकर जनता को गुमराह करना चाहती है। तीनवर्षों में भाजपा सरकार द्वारा कोई उल्लेखनीय विकास कार्य नहीं किये गए जिनका उल्लेख किया जा सके।

उत्तर प्रदेश में भाजपा राज में कानून व्यवस्था एक मजाक बनकर रह गई है। महिलाएं एवं बच्चियां सभी असुरक्षित हैं। हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं थम नहीं रही है। अपराधी बेखौफ हैं। न्याय मांगने पर लाठियां मिलती हैं। अपराध नियंत्रण में अपनी असफलता छुपाने के लिए लगातार फर्जी एनकाउण्टर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बनता जा रहा है। प्रदेश का किसान बदहाल है। सैकड़ों किसान भुखमरी एवं कर्ज के बोझ में दबकर आत्महत्या कर चुके हैं। राज्य में भाजपा सरकार जब से पदारूढ़ हुई है तभी से भाजपा की राजनीति वैमन्यसता, रागद्वेष की है। भाजपा की नफरत की राजनीति का परिणाम है कि समाजवादी

भारत का निर्यात 310339 मिलियन अमेरिकन डालर था और आयात 448033 मिलियन अमेरिकन डालर था और वर्ष 2018-19 में निर्यात 238892 मिलियन अमेरिकन डालर और आयात 361914 मिलियन अमेरिकन डालर था। व्यापार में लगातार घाटा हमारी अर्थनीति की असफलता का द्योतक है। इसी तरह अगर हम दुनिया के प्रमुख देशों के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय प्रतिवर्ष देखें तो स्थिति बिल्कुल साफ हो जायेगी। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष आय 2020 अमेरिकन डालर, श्रीलंका में 4060 अमेरिकन डालर, चीन में 9470 अमेरिकन डालर, रूस में 10230 अमेरिकन डालर, इंग्लैंड में 41340 अमेरिकन डालर और अमेरिका में 62850 अमेरिकन डालर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय है। इसके बावजूद हमारे शासक अमेरिका और चीन के बाद भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताने में कतई संकोच नहीं करते हैं।

सच बात यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है, बैंकें दिवालिया होने के कगार पर हैं और इस बात की आशंका है कि केन्द्र सरकार कुछ दिनों बाद अपने कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में भी नहीं होगी।

कृषि क्षेत्र में लगभग 68 प्रतिशत आबादी की निर्भरता है परन्तु जीडीपी में इसका हिस्सा लगभग 12 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि न हो पाने के कारण किसान बर्बाद हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। बाहर से कृषि उत्पादों का आयात निरंतर बढ़ रहा है जिसका सीधा असर भारत के किसानों पर पड़ रहा है। भारत ने कृषि अनुसंधान पर खर्च करना कम कर दिया है इसलिये नये या अच्छी गुणवत्ता पूर्ण बीजों की उपलब्धता गिर रही है। विदेशी कम्पनियाँ इसलिये हाईब्रिड बीज ऊँची कीमतों पर बेच रहीं हैं। किसानों को एम0एस0पी0 नहीं मिल पा रही है। कृषि सेक्टर जो आज भी 60 फीसदी से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है उसकी स्थिति निरंतर निराशाजनक होती जा रही है। किसानों को लगातार घाटा होने से पूरे देश में निरंतर किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं।

पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न योजनाबद्ध तरीकों से किया जा रहा है। मो. आज़म खां वरिष्ठ नेता हैं, नौ बार विधायक एवं कैबिनेट मंत्री पद पर रहे हैं और वर्तमान सांसद लोकसभा हैं उनको भाजपा सरकार द्वारा जिस तरह अपमानित किया जा रहा है और फर्जी मुकदमों में फंसा कर जेल यातना दी जा रही है वह घोर निन्दनीय है। मो. आज़म खां द्वारा समाजवादी सरकार के कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र के उच्चस्तरीय मौलाना मोहम्मद अली जोहर विश्वविद्यालय की स्थापना भाजपा सरकार की आँख की किरकिरी बन गयी है।

समाजवादी पार्टी की सरकार के समय श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जो उच्चकोटि के जनहित के विकास कार्य हुये थे उनके नाम बदलकर जनता को धोखा देने का कार्य किया जा रहा है।

भाजपा द्वारा उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष में 70 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया था परन्तु 3 वर्षो में रोजगार देने के बजाय 90 हजार होमगार्डो की नौकरी छीन ली है। कई कारखानों बन्द होने से हजारों कर्मचारियों की छटनी कर दी गई। उद्योगों की स्थापना हेतु प्रदेश में निवेश लाने के नाम पर इनवेस्टर्स समिट के आयोजन के नाम पर अरबों रुपया पानी में बहा दिये गये, निवेश शून्य रहा। सरकार केवल झूठे वादों से प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। नौजवान भटक रहे हैं।

समाजवादी पार्टी की सरकार के समय समाज के कमजोर परिवार की महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के

संगठनात्मक ढांचे में बदलाव के लिए संविधान संशोधन

समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी संविधान में संगठनात्मक ढांचे से संबंधित संशोधन भी पारित किए गए।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव द्वारा पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल को संबोधित पत्र में बताया गया है कि राष्ट्रीय सम्मेलन में अनुमोदन की प्रत्याशा में पार्टी संविधान में निम्नलिखित संशोधन पारित हुए हैं जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकते हैं एवं इस संबंध में पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों को सूचित कर दिया जाए।

धारा 3- संगठनात्मक ढांचा

(6) प्रारंभिक समिति के स्थान पर निम्न होंगे-

(6) ब्लाक स्तरीय संगठन

(क) ब्लाक सम्मेलन

(ख) ब्लाक समिति

(7) प्रारंभिक समितियां

(बूथ स्तरीय संगठन)

धारा 8

धारा 8 में निम्न धारा 8 (अ) जोड़ दी जाएगी-

प्रत्येक विकासखण्ड में एक समिति होगी जिसे ब्लाक समिति माना जाएगा।

धारा 9

धारा 9 (6) संशोधित निम्न होगी-

ब्लाक स्तरीय संगठन के अंतर्गत ब्लाक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें ब्लाक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, 5 सचिव सहित कुल 21 सदस्य होंगे।

धारा 10

धारा 10 (3) जिला कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष 3 के स्थान पर 6 तथा सचिव 10 के बजाय 15 होंगे परंतु कार्यकारिणी में कुल

लिए 6 हजार रुपया प्रतिवर्ष समाजवादी पेंशन योजना लागू कर पूरी की गई। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और मेट्रो जैसी शानदार योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। एक्सप्रेस-वे पर वायुसेना के युद्धक विमान और मालवाहक जहाज तक उतर चुके हैं। एक्सप्रेस-वे के किनारों पर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए विश्वस्तरीय मंडियां बनाने की योजना भी थी।

समाजवादी सरकार में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए 1090 वूमेन पावर लाइन बनी। गंभीर बीमारियों-कैंसर, दिल, लीवर, किडनी के मुफ्त इलाज की व्यवस्था हुई। समाजवादी सरकार में मरीजों, दुर्घटना में घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए 108 नम्बर समाजवादी एम्बूलेंस सेवा, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को अस्पताल लाने-ले जाने के लिए 102 नंम्बर सेवा शुरू हुई। लखनऊ में एशिया के सबसे बड़े 350 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में जनेश्वर मिश्र पार्क की स्थापना और अन्तरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम के निर्माण जैसे अद्वितीय कार्य पूरे हुए।

समाजवादी सरकार में किसानों की 50 हजार रुपए तक कर्जमाफी के साथ मुफ्त सिंचाई की सुविधा दी गई। किसानों को दुर्घटना बीमा का लाभ मिला। जिला मुख्यालयों को चार लेन सड़कों से जोड़ा गया। 18 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क लैपटाप, कन्या विद्याधन, समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना, कौशल विकास प्रशिक्षण जैसी तमाम योजनाएं समाजवादी सरकार में लागू की गई। अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया गया। बजट का 75 प्रतिशत अंश किसानों की तरक्की और कृषि उन्नति पर खर्च के लिए व्यवस्था की।

समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का दायित्व है कि उत्तर प्रदेश के किसानों, नौजवानों, अल्पसंख्यकों, व्यापारियों, महिलाओं, छात्रों आदि सभी वर्गों को न्याय दिलाने तथा प्रदेश के विकास के लिए पार्टी के कार्यकर्ता अभी से बूथस्तर तक पहुँचकर आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की

सदस्य संख्या 51 ही रहेगी।

धारा 30 सम्बद्ध संगठन

समाजवादी अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ के स्थान पर निम्नलिखित संगठन होंगे-

(क) समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ

(ख) समाजवादी अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

मो. आज़म खां वरिष्ठ नेता हैं, नौ बार विधायक एवं कैबिनेट मंत्री पद पर रहे हैं और वर्तमान सांसद लोकसभा हैं उनको भाजपा सरकार द्वारा जिस तरह अपमानित किया जा रहा है और फर्जी मुकदमों में फंसा कर जेल यातना दी जा रही है वह घोर निन्दनीय है।

तैयारी में जुटने हेतु कार्यक्रम एवं रणनीति तैयार करें ताकि भाजपा की जन विरोधी, विकास विरोधी तथा प्रदेश के समाज को बांटने वाली सरकार को सत्ता से दूर किया जा सकें इससे समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

समाजवादी पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में वैकल्पिक राजनीति के लिए कारगर कदम उठाने का निर्णय लिया गया।

समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति आह्वान करती है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के होने वाले 2022 के चुनावों में श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनने वाली समाजवादी सरकार को प्रचण्ड बहुमत प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ता पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जी-जान से जुट जायें।

अखिलेश जी ही दिला सकते हैं दलितों-पिछड़ों को उनका हक

*समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव **इंद्रजीत सरोज** का मानना है कि दलितों, पिछड़ों को उनका हक समाजवादी पार्टी ही दिला सकती है। लिहाजा इस समाज से जुड़े लोगों को 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने में जुटना चाहिए। पेश है वरिष्ठ पत्रकार **रंजीव** से उनकी खास बातचीत:*

अपने अब तक के राजनीतिक सफर के बारे में कुछ बताइए।

वर्ष 1983 में मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और वहीं बहुजन मूवमेंट में भाग लेने लगा। मान्यवर कांशीराम के संपर्क में आया व बामसेफ के साथ काम करने लगा। उसी दौरान बहुजन समाज पार्टी का भी गठन हुआ और मैं पढ़ाई के साथ उससे जुड़कर अपनी राजनीतिक गतिविधियों में भी लगा रहा। कांशीराम जी ने मुझे मंझनपुर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी देते हुए कहा कि वहां चुनाव लड़ने की तैयारी तैयारी

करूं। साल 1991 में मंझनपुर से चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। उसके बाद से मैं मंझनपुर में चार बार जीता, बसपा की सरकारों में मंत्री भी रहा व पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया। अगस्त 2017 में बसपा छोड़ने का निर्णय लिया और फिर बहुत सोच-विचार कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ। सोच-विचार का निष्कर्ष यह था कि जिस बुनियादी विचारधारा के साथ बसपा का गठन हुआ था वही सोच समाजवादी पार्टी की भी है और समाजवादी पार्टी ही दबे-कुचले, दलितों, पिछड़ों के हित में राजनीति कर रही है एवं उन्हें आगे बढ़ाना चाहती है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिला और उनसे बात करने के साथ ही तुरंत फैसला लिया कि मुझे सपा में शामिल होना है और मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूं।

वर्तमान राजनीतिक माहौल में गरीबों, खासकर दलितों की क्या स्थिति दिख रही है?

दलित, पिछड़ा, गरीब बहुत छला गया है। उसे कुछ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 3 साल हो गए लेकिन समाज के इस तबके को भाजपा से छलावे के अलावा कुछ नहीं मिला। विकास हुआ नहीं, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार के फैसलों को रोजी-रोटी से जोड़ने की जो प्रक्रिया शुरू की थी वह योगी सरकार में ठप है। अब तो संविदा पर भर्तियां भी बंद हैं और सारा जोर आउटसोर्सिंग पर लगा है। इसलिए लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं। मेरे जैसे लोग गांव-देहात की राजनीति करते हैं और जमीन पर यही पाते हैं कि गरीबों को रहने के लिए न तो अच्छे मकान मिले और शौचालय के नाम पर तो मजाक बनाया गया। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन हाथी का दांत हो गए। एक बार मिलने के बाद भरवाने की जिम्मेदारी

बसपा जिस मिशन को लेकर बनी थी व चली थी उसे अंजाम तक पहुंचाने का माद्दा उत्तर प्रदेश में अगर किसी राजनेता में है तो वे श्री अखिलेश यादव ही हैं। यही वजह है कि बसपा के लोगों का एक बड़ा तबका ऐसा है जो अखिलेश जी को और उनकी सोच को अपनी विचारधारा के करीब पाता है और वह समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है।

गरीबों को दे दी गई लेकिन इतना महंगा सिलेंडर कौन गरीब भरा पाएगा? इतना ही नहीं, इस सरकार ने गरीब की झोपड़ी में बिजली का मीटर लगा दिया लेकिन कनेक्शन नहीं दिया। बिजली का बिल लेकिन आने लगा। यह है भाजपा के राज में गरीबों, दलितों की स्थिति।

दलित समाज का बड़ा तबका बसपा से निराश होकर सपा से जुड़ रहा है। इनमें बसपा के कई कद्दावर नेता भी हैं। इसी क्या वजह देखते हैं आप?

मैंने साल 2012 से 2017 के बीच अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते हुए देखा है। विधानसभा में उनके वक्तव्य सुने हैं। उनके वक्तव्यों में उत्तर प्रदेश को वास्तविक रूप से विकसित करने की ललक और दलितों-पिछड़ों के लिए दर्द झलकता था। वे एक विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का विचार लेकर चल रहे थे जिसमें लोग तरक्की करें और खुशहाल रहें। वे ऐसा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं जिस पर यूरोप और अमेरिका के विकास की छाप हो। ऐसी प्रगतिशील विचारधारा का व्यक्ति ही गरीबों का उत्थान कर सकता है। बसपा जिस मिशन को लेकर बनी थी व चली थी उसे अंजाम तक पहुंचाने का माद्दा उत्तर प्रदेश में अगर किसी राजनेता में है तो वे श्री अखिलेश यादव ही हैं। यही वजह है कि बसपा के लोगों का एक बड़ा तबका ऐसा है जो अखिलेश जी को और उनकी सोच को अपनी विचारधारा के करीब पाता है और वह समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है। मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी और लोग जुड़ेंगे। जो भी व्यक्ति मूल रूप से बसपा का है वह भाजपा या कांग्रेस में नहीं बल्कि अखिलेश जी के नेतृत्व में उनसे जुड़ना चाहेगा क्योंकि उसे पता है कि कांग्रेस अगर सांपनाथ है तो भाजपा नागनाथ। यह दोनों पार्टियां कभी भी गरीबों दलितों और पिछड़ों का उत्थान नहीं करेंगी। इसलिए उसकी पसंद सपा है।

आपने दलितों के बीच बहुत काम किया है। बसपा में आप प्रमुख दलित नेताओं में शामिल थे। अब सपा में आने के बाद अखिलेश जी के साथ काम करते हुए आप खुद को कितना सहज महसूस करते हैं?

अखिलेश जी में हर मुद्दे पर बेहद सहजता है। उनसे किसी भी मुद्दे पर बात की जा सकती है। उनसे बहुत सुगमता और सरलता से मिला जा सकता है और वे बेहद सभ्य और शालीन व्यक्तित्व वाले नेता है। अखिलेश यादव जी में मुझे पूरा लोकतंत्र दिखाई पड़ता है। वह लोकतंत्र लागू करना चाहते हैं इसलिए सबकी राय लेते हैं और सबकी सुनते हैं। उनके साथ काम करने में किसी तरह की हिचक नहीं होती। वे बेहद शालीन, सौम्य, सहज एवं सरल व्यक्तित्व के तो हैं ही साथ ही अत्यंत विजनरी सोच वाले प्रगतिशील नेता भी हैं। उनके साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य एवं गर्व की बात है।

अखिलेश जी से ही उम्मीद है कि वे इन दोनों के विचारों को एक साथ लेकर आगे चल सकते हैं।

भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति को कैसे परास्त करेंगे? गरीबों, वंचितों एवं दलितों-पिछड़ों को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति से भरमाने का यह दौर कितना जटिल है?

2022 का चुनाव अखिलेश जी के नाम व उनके चेहरे पर होगा और लोग उनके लिए वोट करेंगे। जनता को बतौर मुख्यमंत्री उनके किए काम याद हैं।

देखिए, जनता अब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति से जुड़े मुद्दों से हटना चाहती है। उसे अब विकास, रोजी-रोटी व तरक्की चाहिए। जनता अब इन मुद्दों पर सोचने लगी है। जनता समझने लगी है कि सांप्रदायिक राजनीति की आड़ में उसके हक मारे जा रहे हैं। इसलिए वह अब पाकिस्तान, हिन्दू-मुस्लिम, मंदिर-मस्जिद जैसे भाजपा के भरमाने वाले मुद्दों को समझने लगी है। खास तौर पर दलितों-पिछड़ो को यह दिखने लगा है कि देश के बड़े-बड़े सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हैं। उन्हें यह बखूबी समझ में आ रहा है कि जब सरकारी संस्थान रहेंगे ही नहीं तो उनके लिए आरक्षण कैसे रहेगा? यही वजह है कि जनता अब भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति वाले पत्थर से ठोकर खाकर अब बार-बार गिरने को तैयार नहीं। वह इस पत्थर को अपने रास्ते से हटाना चाहती है।

बाबा साहब भीमराव अंबेडकर व डा. राम मनोहर लोहिया की विचारधारा में क्या समानताएं देखते हैं आप ?

दोनों विभुतियां गरीबों की हितैषी एवं शुभचिंतक थीं। दोनों ही गरीबों एवं वंचितों के हित व उन्हें उनका हक दिलाने के प्रबल पैरोकार थे। अखिलेश जी बधाई के पात्र हैं कि वे बाबा साहब व डा. लोहिया के विचारों को साथ लेकर चल रहे हैं इसलिए वे कहते भी हैं कि समाजवादी साइकिल का एक पहिया डा. अंबेडकर एवं दूसरा पहिया डा. लोहिया की विचारधारा का वाहक है। इसलिए आज दलित समाज को भी

क्या आपका मानना है कि आरक्षण को खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं?

कोशिश नहीं बल्कि साजिश हो रही है। कान को घुमाकर पकड़ा जाए या सीधे, बात एक ही होती है। यह जो भाजपा के राज में सरकारी संस्थानों, उपक्रमों को धड़ल्ले से बेचने की प्रक्रिया चल रही है वह व आरक्षण खत्म करने की साजिश का ही हिस्सा है। भाजपा इसी तरह आरक्षण को खत्म करना चाहती है।

आप लंबे समय से राजनीति में हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव की क्या तस्वीर देखते हैं?

जिस तरह साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को नरेन्द्र मोदी के नाम पर वोट मिला ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश में 2022 में जनता श्री अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए मतदान करेगी। 2022 का चुनाव अखिलेश जी के नाम व उनके चेहरे पर होगा और लोग उनके लिए वोट करेंगे। जनता को बतौर मुख्यमंत्री उनके किए काम याद हैं। यदि भाजपा झूठ फैलाकर सरकार बना सकती है तो

दलित समाज को मैं यह कहना चाहूंगा कि उनका भला न तो कांग्रेस ने किया है और न भाजपा कर रही है। दलित समाज अब बसपा से कोई उम्मीद न रखे।

समाजवादियों के पास तो सच बोलने के लिए बहुत सारी उपलब्धियां एवं उसी सच की सहायता से सरकार बनाने का हौसला है।

उत्तर प्रदेश के दलित समाज के लिए आपका क्या संदेश है?

दलित समाज को मैं यह कहना चाहूंगा कि उनका भला न तो कांग्रेस ने किया है और न भाजपा कर रही है। दलित समाज अब बसपा से कोई उम्मीद न रखे। बसपा की नेता ने खुद को समेट लिया है और भाजपा के इशारे पर काम कर रही हैं। उनके नेतृत्व से दलितों, वंचितों, गरीबों का कोई भला नहीं होगा। इसलिए इस तबके के हर व्यक्ति से मेरा अनुरोध है कि जो सही सोच वाले इनसान हैं, जिनके मन में दलितों-वंचितों के लिए दर्द है, वैसे नेता यानी श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में दलित समाज को एकजुट होकर अपनी सरकार बनाने के काम में लगना चाहिए। इस समाज ने कांग्रेस को देख लिया, भाजपा को देख ही रहे हैं तो निराशा के इस माहौल से निकलने के लिए अखिलेश जी के कराए कामों, उनकी सरकार की योजनाओं को देखें व अखिलेश जी के साथ जुड़ कर उन्हें अवसर दें।

महोबा में 66 किसानों ने की आत्महत्या परिजनों के साथ खड़ी हुई सपा

भाजपा सरकार में किसानों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। किसानों को फसल की लागत का डयोढ़ा मूल्य देने, गन्ना किसानों के बकाया के साथ ब्याज अदा करने, किसानों की आय दोगुनी करने जैसे लुभावने वादों पर कोई अमल नहीं। अलबत्ता महंगाई की चोट ने किसानों पर दोहरी मार जरूर कर दी। इस सबसे परेशान और बदहाल किसानों को आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा है। ऐसे किसानों के परिजनों के साथ समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी हो रही है व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर उनकी मदद कर रही है।

किसानों को मदद की इसी कड़ी में सपा के विधायकों का प्रतिनिधिमंडल 29 फ फरवरी 2020 को बुंदेलखंड गया एवं महोबा के विभिन्न विकास खंडों में उन किसानों के घर पहुंचा, जिन्होंने भाजपा सरकार के कार्यकाल में पिछले कुछ महीनों आत्महत्या कर ली है। उल्लेखनीय है कि श्री अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व में समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा मिली थी। कर्जमाफी और फसल बीमा का लाभ मिला था। महोबा में किसानों को राहत पैकेज में खाद्य सामग्री दी गई थी और पेयजल पहुँचाया गया था।

श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के विधायकों ने कबरई, पनवाड़ी, चरखारी और जैतपुर विकासखंडो के गांवों में पहुंचकर आत्महत्या करने वाले 66 किसानों के परिजनों से मुलाकात की। उनके प्रति संवेदना जताते हुए परिवार की आर्थिक मदद की। भाजपा सरकार के कार्यकाल में विकास खंड पनवाड़ी में 13, विकास खंड जैतपुर में 16, विकास खंड

चरखारी में 14 और विकास खंड कबरई में 23 किसानों ने आत्महत्या की है। इन प्रभावित परिवारों ने बताया कि सरकार का कोई मंत्री या प्रतिनिधि उनके यहां शोक व्यक्त करने तक नहीं पहुंचा, मदद की बात तो दूर।

महोबा के कबरई विकास खंड में किसानों की मृत्यु की वजहों की जांच करने और परिजनों से संवेदना जताने व मदद के लिए विधायक नरेन्द्र वर्मा, राजकुमार राजू, बृजेश कठेरिया तथा एमएलसी डा.राजपाल कश्यप, हीरालाल यादव उनके घर पहुंचे। इसी तरह पनवाड़ी विकास खंड में विधायक अमिताभ वाजपेयी, इरफान सोलंकी एवं रमेश मिश्र ने पहुंचकर आत्महत्या करने वाले किसान परिवारों से मुलाकात की।

चरखारी विकास खंड में एमएलसी शशांक यादव, उदयवीर सिंह व सुनील सिंह साजन ने जबकि जैतपुर विकास खंड में एमएलसी आनंद भदौरिया, संतोष यादव सनी, राजेश यादव तथा दिलीप उर्फ कल्लू यादव ने गांव पहुंचकर किसान परिवारों से मुलाकात की व उनकी मौत के कारणों की जानकारी हासिल करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से संवेदना जताते हुए अर्थिक मदद दी।

इन मृतक किसानों के परिजनों की मदद की गई

विकास खंड- कबरई

1. मृतक प्रीतम कोरी- ग्राम-बिलरही
2. मृतक हजारी लाल कुशवाहा- ग्राम-भैरवगंज श्रीनगर
3. मृतक श्यामलाल अहिरवारा- ग्राम-बरा
4. मृतक रामआसरे विश्वकर्मा- ग्राम-बरा
5. मृतक कुंवर बाई- ग्राम-बिलरही
6. मृतक दयाशंकर कुशवाहा- ग्राम-श्रीनगर
7. मृतक ज्ञानेन्द्र सिंह- ग्राम-बिलरही
8. मृतक रामदयाल अनुरागी- ग्राम-बन्नी
9. मृतक बाबू राम कुशवाहा- ग्राम-परसहा
10. मृतक सुरेन्द्र कुमार श्रीवास- ग्राम-ज्योड़ी
11. मृतक बद्दू अनुरागी- ग्राम-सुरहां
12. मृतक दयाराम सिंह- ग्राम-सुरहां
13. मृतक बरदानी लाल- ग्राम-खन्ना
14. मृतक जगदीश प्रजापति ग्राम-खन्ना
15. मृतक चन्द्रभान- ग्राम-तमौरा
16. मृतक दुलीचन्द अहिरवार- ग्राम-करहरा कलां
17. मृतक राजबहादुर श्रीवास- ग्राम-करहरा कलां "
18. मृतका कुन्ती देवी- ग्राम-कादी पहाड़ी
19. मृतक नृपत राजपूत- ग्राम-तिसरापुर
20. मृतक चन्द्र पाल- ग्राम-किड़ारी
21. मृतक गंगादीन अहिरवार- ग्राम-बहावा
23. मृतक नत्थू- ग्राम-गहरा
24. मृतक जगरूप यादव- ग्राम-किड़ारी

विकास खंड- पनवाड़ी

1. मृतक सुरेन्द्र सुल्लेरे ग्राम- पाठकपुरा पनवाड़ी
2. मृतक शिव कुमार श्रीवास- ग्राम-किल्हौवा
3. मृतक दिनेश कुमार राजपूत-ग्राम-जखा
4. मृतक शिवराम लोधी- ग्राम-सलैया खालसा
5. मृतक हरिराम- ग्राम-सलैया खालसा
6. मृतक केधीलाल बपिता- ग्राम-गडौरा
7. मृतक राम स्वरूप निरंजन- ग्राम-रूटीकलां
8. मृतक खूबचन्द्र कुशवाहा- ग्राम-धवार
9. मृतक रामहेत लोधी- ग्राम-रिवई
(थाना महोबा कंठ)
10. मृतक भतुरईया उर्फ चतुर्भज -ग्राम-भरवारा
11. मृतक हृदेश द्विवेदी- ग्राम-विजयपुर
12. मृतक गजाधर यादव- ग्राम-विजयपुर

विकास खंड- चरखारी

1. रामरतन कुशवाहा- ग्राम- बराय
2 मुन्नालाल जोशी- ग्राम- मु. सादराय खरेला
3 अरविन्द तिवारी- ग्राम- मु. स्वामीदीन खरेला
4 रामेश्वर- ग्राम-बैहारी
5 सुधीर सिंह- ग्राम- बल्लाय
6. खेमचन्द्र- ग्राम- अमरगंज
7. हेमरानसूत- ग्राम- गौरहारी

8.रघुवीर पाल- ग्राम- अकढौहा अठगोहा
9. प्रहलाद सिंह- ग्राम- अकढौहा अठगोहा
10.कृपाल राजपूत- ग्राम- कुडार
11.अशर्फी लाल- ग्राम-नरेडी
12.भुज्जीलाल- ग्राम-जतौरा
13.राधिका सोनी- ग्राम-रिबई
14.रामदूत यादव- ग्राम-टूमिया डाँग

विकास खंड- जैतपुर

1. कालका प्रसाद- ग्राम- मु.राजावार्ड, कुलपहाड़
2. रामविशाल सोनी- ग्राम- मु.राजावार्ड, कुलपहाड़
3. कल्लू यादव- ग्राम-लाडपुर
4. दिनेश कुमार सुलोरे- ग्राम-लाडपुर
5. सलीम मंसूरी- ग्राम-जैतपुर
6. आशाराम यादव -ग्राम- मु.घुसियाना, जैतपुर
7. मनोज यादव- ग्राम- कैधौरा
8. राधेलाल- ग्राम- टिकरिया
9. लखनलाल राजपूत- ग्राम-बेरी
10. सुखसिंह श्रीवास-ग्राम-बौस सतारी
11. धनिया उर्फ धनीराम- ग्राम-सतारी

12. रामनारायण नायक- ग्राम-लेवा
13. खेत सिंह- ग्राम-बुधौरा
14. नोमीचन्द- ग्राम- खमा
15. शारदा- ग्राम- स्यावन
16. श्रीमती प्रेमा सवोर- ग्राम-मऊपुरी

डा. राम मनोहर लोहिया जयंती पर विशेष

मौजूदा दौर में ज्यादा प्रासंगिक है सप्त क्रांति

रविकान्त

सहायक प्रोफेसर, हिन्दी, लखनऊ विवि

आजादी की लड़ाई के महान योद्धा और समाजवादी चिंतक डॉ. राममनोहर लोहिया 23 मार्च 1910 को फैज़ाबाद जिले के अकबरपुर में पैदा हुए। उन्हें उनके जीवन संघर्ष , विचारधारा और मौलिक चिंतन के लिए जाना जाता है। उन्होंने जिस राजनीतिक धारा को स्थापित किया, वह समूचे उत्तर भारत में आज भी मजबूती के साथ मौजूद है। लोहिया जी की राजनीतिक धारा सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, मजबूत लोकशाही और संसदीय व्यवस्था के लिए विख्यात है। स्वतंत्र भारत में उनके राजनीतिक आदर्शों को संविधान और संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मार्फत स्थापित किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था और जिला परिषदों का गठन लोहिया जी कल्पित चौखंभा राज की याद दिलाता है। उनके मतानुसार स्वस्थ और सफल लोकतंत्र की बुनियाद स्वायत्त संस्थाओं और सत्ता के विकेन्द्रीकरण में निहित है।

डा.लोहिया का अपने आरंभिक जीवन में ही स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़ाव हुआ। अपने पिता के साथ वे गाँधी जी से मिले। छात्र जीवन में वे अवध के किसान आंदोलन से जुड़े रहे। इसी दरम्यान वे उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी चले गये। वहां से लौटने बाद लोहिया जी गाँधी जी के नेतृत्व में चल रहे स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े, लेकिन वे कांग्रेस के वर्गीय चरित्र को भी देख

रहे थे। कांग्रेस के साथ पूंजीपति, राजा-महाराजा,सेठ-साहूकार और सामंत भी जुड़े हुए थे। डा. लोहिया के सामने यह सवाल था कि कांग्रेस के नेतृत्व में मिलने वाली आजादी क्या सच्ची आजादी होगी! आजादी का मतलब केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है। देश के लाखों करोड़ों स्त्री,दलित,आदिवासी,मजदूर और किसान जब मुक्त होंगे तभी आजादी का असली मतलब होगा।

लोहिया जी ने देखा कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात को राजनीतिक आजादी तो मिल गई लेकिन सामाजिक और आर्थिक आजादी के प्रश्न अभी भी बाकी हैं। संविधान सभा में इन प्रश्नों पर बहस और चिंतन- मनन जरूर हुआ। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जैसे अनेक प्रावधानों के माध्यम से इन प्रश्नों के राजनीतिक और प्रशासनिक समाधान करने की भी कोशिश की गई । लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार और प्रशासन सामाजिक और आर्थिक आजादी के लिए अक्षम साबित हुए। इसलिए राजनीतिक आजादी के बाद भी लोहिया जी इन प्रश्नों पर संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करते रहे । दरअसल, वे आदर्श नहीं यथार्थ के कायल थे।

डॉ राममनोहर लोहिया बीसवीं शताब्दी के भारत के अनूठे व्यक्तित्व हैं।उनके भीतर भारतीय संस्कृति के विशिष्ट मूल्यों के साथ -साथ पूरी दुनिया की श्रेष्ठ मानवीय विशेषताओं का समावेश है। समाजवादी चिंतक आनंद कुमार डॉ लोहिया का विशिष्ट अंदाज में परिचय देते हुए लिखते हैं, "डॉ लोहिया राम के अवध में जन्मे। सीता की मिथिला में उनका ननिहाल था। कृष्ण की कथा उन्हें आनंद में सरोबार करती थी और गोवर्धन, ब्रज,द्वारिका से लेकर मणिपुर तक कृष्ण की लीला वे बार-बार याद करते थे। बुद्ध, कबीर,तुलसी की काशी और विवेकानद, अरविंद,टैगोर,सुभाष के कलकत्ता में पढ़कर बड़े हुए थे। फिर यूरोपीय सभ्यता की दार्शनिक धुरी जर्मनी में उच्च शिक्षा पूरी कर गांधी और नेहरू के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़कर भारतीय समाज और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए जोखिम भरे राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े।" अपने पिता के साथ गांधी के सत्याग्रह और आंदोलन में शामिल होने वाले डा. लोहिया ने जर्मनी में बर्लिन से 'नमक सत्याग्रह के अर्थशास्त्र' पर पीएच.डी. की डिग्री हासिल की। जर्मनी में रहने के दौरान उन्होंने पूरे यूरोप का भ्रमण करते हुए साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के शोषण तंत्र को यथार्थपरक ढंग से समझा था। इसीलिए भारत लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन की धारा में समाजवादी विचारों के साथ नए भारत के निर्माण का सपना सृजित किया।

भारत के स्वाधीनता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के शहीदों का सपना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र बनाना था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह , सुखदेव और राजगुरू को फांसी हो गई ।इसके पहले क्रांतिकारियों ने 1928 में फिरोजशाह कोटला की बैठक में अपने पूर्व संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर लिया था। इसके मुख्य कमांडर चंद्रशेखर आजाद और मुख्य विचारक भगत सिंह के शहीद होने के बाद यह धारा लगभग खत्म हो गयी। क्रांतिकारियों के सपनों को साकार करने के लिए डा. लोहिया आगे आए। लोहिया जी ने 23 मार्च को भगत सिंह,सुखदेव और राजगुरू की फांसी के कारण अपना जन्मदिन मनाना बंद कर दिया। वास्तव में डॉ लोहिया ने क्रांतिकारियों के विचारों को कांग्रेस की धारा के साथ जोड़ने का काम किया। 1934 में उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण में साथ मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। गांधी जी के तमाम आंदोलनों में वे साथ रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में

"

डॉ राममनोहर लोहिया बीसवीं शताब्दी के भारत के अनूठे व्यक्तित्व हैं।उनके भीतर भारतीय संस्कृति के विशिष्ट मूल्यों के साथ -साथ पूरी दुनिया की श्रेष्ठ मानवीय विशेषताओं का समावेश है।

जब गाँधी,नेहरू समेत तमाम नेता अंग्रेज हुकूमत द्वारा गिरफ्तार कर लिए गये तब भूमिगत रहकर डा. लोहिया ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया।

आजादी के आंदोलन के सम्मुख आने वाली चुनौतियों से भी वे लगातार जूझ रहे थे। साम्प्रदायिक राजनीति इस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी। हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग की कट्टर सांप्रदायिक राजनीति के कारण हिन्दू-मुस्लिम नाहक ही एक दूसरे के दुश्मन बन रहे थे। सांप्रदायिक दंगों की आग में देश जल रहा था। डा.लोहिया गाँधी जी के साथ दंगाग्रस्त इलाकों में शांति और सद्भाव कायम करने के लिए जाते थे। 15 अगस्त 1947 को जब दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था तब लोहिया जी, गाँधी जी के साथ बंगाल में सांप्रदायिकता की आग बुझाने में लगे थे। एक ऐसे वक्त में डा. लोहिया गाँधी के साथ थे जब गाँधी जी के जीवन के सारे आदर्श धू-धू करके राख हो रहे थे और गाँधी निहत्थे चट्टान की तरह उन्हें बचाने में लगे हुए थे। उस दौर में डा. लोहिया द्वारा साथ चलने के इन लम्हों को इतिहासकारों ने अक्सर नजरअंदाज किया है लेकिन आज का बांगलादेश लोहिया के इन कामों को बड़ी शिद्दत के साथ याद करता है।

नोआखली और कलकत्ता में साप्रदायिक पागलपन को दूर करके शांति और सद्भाव कायम करते हुए गाँधी और लोहिया जी दिल्ली लौटे। 30 जनवरी 1948 को गाँधी जी के बुलावे पर लोहिया जी उनसे मिलने

> **"लोहिया जी भारतीय संस्कृति और उसके मिथकों से समाज और राजनीति के संबंध जोड़ते थे। वे राजनीति के साथ धर्म को गड्डमड्ड नहीं करते थे**

जा ही रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि एक कट्टरपंथी हिन्दू नाथूराम गोड्से ने गाँधीजी की हत्या कर दी है। सांप्रदायिकता और विभाजन के लिए हिन्दू महासभा की राजनीति को जिम्मेदार ठहराते हुए लोहिया जी ने अपनी किताब 'भारत विभाजन के गुनहगार' में लिखा है ,"हिन्दू कट्टरवाद उन शक्तियों में शामिल था जो भारत के विभाजन का कारण बनीं।...जो लोग आज चिल्ला- चिल्लाकर अखंड भारत की बात कर रहे हैं अर्थात आज का जनसंघ और उसके पूर्ववर्तियों, जो हिन्दू धर्म की गैर हिन्दू परंपरा के वाहक थे, ने भारत का विभाजन करने में अंग्रेजों और मुस्लिम लीग की मदद की। उन्होंने कतई यह प्रयास नहीं किया कि हिन्दू और मुस्लिम नजदीक आएं और एक देश में रहें।बल्कि उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों के परस्पर संबंधों को खराब करने के लिए हर संभव प्रयास किए।और दोनों समुदायों के बीच यही अनबन और मनमुटाव भारत के विभाजन की जड़ बनी।"

ध्यान देने की बात यह है कि आज नए रूप में ये सांप्रदायिक शक्तियां हमारे सामने हैं। इतिहास की गलत व्याख्या करके हिन्दू और मुसलमानों के मन में एक दूसरे के प्रति घृणा और नफरत पैदा की जा रही है। इससे दोनों समुदायों में दूरियाँ बढ़ी हैं। आशंका और गलतफहमियों के कारण परस्पर विश्वास दरक रहा है। जबकि आजादी के आंदोलन में बनी एकता आजाद हिन्दुस्तान के लिए

भी उतनी ही जरूरी है। लोहिया जी ने दोनों ही समुदायों को फटकारते हुए आजादी का पाठ पढ़ाया है- " जो हिन्दू रजिया, शेरशाह ,जायसी और रहीमन को अपना पुरखा मानने से इनकार करता है वह हिन्दू हिन्दुस्तान की आजादी की कभी रक्षा नहीं कर सकता ; जो मुसलमान गजनी, गौरी और बाबर को अपना पुरखा मानता है और उन्हें विदेशी हमलावर और लुटेरा कहने से इनकार करता है वह मुसलमान आजादी का मतलब नहीं समझता और आजादी की कभी रक्षा नहीं कर सकता।"

लिहाजा जरूरत मिल जुलकर एक मजबूत राष्ट्र बनाने की है। देश का कोई हिस्सा या समुदाय अगर विकास की धारा में पिछड़ जाता है तो देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। दंगों की वजह से जान माल का नुकसान तो होता ही है देश की एकता ,अखंडता,भाईचारे और सौहार्द की बुनियाद भी कमजोर होती है। नफरत और घृणा के माहौल में पलने वाले लोग महत्वहीन सभ्यता और बिखरे हुए राष्ट्र का निर्माण करते हैं।

डा.लोहिया गाँधी जी के विचारों और आदर्शों के प्रशंसक रहे लेकिन अंध समर्थक नहीं। लोहिया जी खुद को गाँधी का 'कुजात' शिष्य कहते थे। चर्चित सोशलिस्ट चिंतक और लोहियावादी मूल्यों के वाहक किशन पटनायक कहते हैं कि एक 'सच्चा शिष्य' हमेशा अपने गुरू का 'विकृत' रूप होता है। लोहिया जी खादी पहनते थे लेकिन चर्खा कभी नहीं कातते थे। गाँधी पक्के सनातनी थे लेकिन लोहिया नास्तिक। अलबत्ता लोहिया जी भारतीय संस्कृति और उसके मिथकों से समाज और राजनीति के संबंध जोड़ते थे। वे राजनीति के साथ धर्म को गड्डमड्ड नहीं करते थे बल्कि उनके लिए " धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म। धर्म श्रेयस की उपलब्धि का प्रयत्न करता है ,राजनीति बुराई से लड़ती है।" वे समकालीन परिस्थितियों पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं," हम आज एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में हैं, जिसमें कि बुराई से विरोध की लड़ाई में धर्म का कोई वास्ता नहीं रह गया है और वह निर्जीव हो गया है, जबकि राजनीति अत्यधिक कलही और बेकार हो गयी है।" आज की परिस्थितियांज्यादा मुश्किल और गंभीर हैं।इसीलिए लोहिया के विचारों की प्रासंगिकता और भी बढ़ गयी है।

किशन पटनायक कहते हैं कि "लोहिया ने गाँधी से एक बहुत बड़ा गुण ग्रहण किया था- अपरिग्रह। मृत्यु से सिर्फ चार वर्ष पहले वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। इसके पहले उनके पास किराए का मकान तक नहीं था और न ही बैंक में कोई खाता। युसूफ़ मेहरअली उन्हें 'प्यारा आवारा' कहा करते थे। मृत्यु के समय उनके पास जो कुछ व्यक्तिगत माल-असबाब था वह यात्रा में काम आने वाले एक बक्से और किताबों के सिवाय और कुछ नहीं था।" लेकिन वे दुनिया के सभी लोगों को खुशहाल देखना चाहते थे। उनके समाजवाद के तीन आधार मूल्य हैं-स्वतंत्रता,समता और संपन्नता। लोहिया जी ने

पूरी दुनिया में इन मूल्यों की स्थापना के लिए सप्त क्रांति का आह्वान किया -स्त्री पुरुष भेदभाव से मुक्ति ,रंग और नस्ल पर आधारित भेदभाव से मुक्ति, जातिगत भेदभाव से मुक्ति,औपनिवेशिक गुलामी से मुक्ति,निजी पूँजी और आर्थिक असमानता से मुक्ति, निजता के हनन से मुक्ति और अस्त्र-शस्त्र यानी हिंसा से मुक्ति। क्या इन भेदभावों से दुनिया को मुक्ति मिल गयी है? स्त्री उत्पीड़न,जातिगत अन्याय, निजता का हनन से लेकर परमाणु बमों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि दुनिया अमानवीयता के मुहाने पर खड़ी है। तमाम तकनीकी और वैज्ञानिक विकास के बावजूद इक्कीसवीं सदी में भी गरीबी,शोषण और अन्याय जारी है। स्वतंत्रता,समता और संपन्नता के साथ -साथ सहिष्णुता,सौहार्द और शांति स्थापित करने के लिए लोहिया जी के दिखाए रास्ते पर चलकर बेहतर दुनिया को बनाया जा सकता है।

जिंदा कौमें पाँच साल इंतजार नहीं करतीं!

(यह लेखक के अपने विचार हैं।)

जनेश्वर मिश्र पार्क, लार्ड खालिद और अखिलेश जिंदाबाद के नारे !

लंदन की मशहूर शख्सियत लार्ड डॉ खालिद हमीद लंदन से लखनऊ आए तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि जनेश्वर मिश्र पार्क घूमा जाए। इस पार्क के बारे में उन्होने काफी कुछ सुन रखा था एवं उनके कई परिचितों ने भी पार्क की जो प्रशंसा की थी। उससे उनकी जिज्ञासा बढ़ी हुई थी। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव तक पहुंची तो वे स्वयं लार्ड हमीद को पार्क दिखाने को तैयार हो गए।

लार्ड हमीद जब जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे तो इसकी विशालता, हरी भरी हरियाली और आकर्षक वातावरण से प्रभावित होकर कहने लगे कि यह पार्क तो लंदन के विख्यात हाइड पार्क जैसा है। डॉ हमीद ने पानी से भरी झील, आकाश में लहराते राष्ट्रीय ध्वज को देखकर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने अखिलेश जी को बधाई दी कि उनके मुख्यमंत्रित्वकाल में 500 एकड़ में बने जनेश्वर मिश्र पार्क से पर्यावरण एवं प्रकृति का सुंदरतम रूप निखर कर आया है। अखिलेश जी ने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर जनेश्वर मिश्र पार्क में प्रवेश निःशुल्क होगा। भारत में यह सबसे बड़ा पार्क है।

जनेश्वर मिश्र पार्क में भ्रमण के दौरान अखिलेश जी को देख कर बड़ी तादाद में युवा एकत्र होकर उनके जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। कई बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो महिलाओं ने फिर दोबारा सरकार में आने की कामना की। गोण्डा से आए पंडित टीएन त्रिपाठी का कहना था कि अखिलेश जी आपके कार्यकाल में ही

समाजवादी सरकार द्वारा निर्मित इस पार्क का अनावरण वर्ष 2014 में हुआ था। पार्क तकरीबन 376 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है।

जनहित के काम हुए थे। समाजवादी सरकार में हुए विकास कार्य ही आज भी दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी है। अब सभी लोग आपकी सरकार आने का इंतजार कर रहे हैं।

श्री त्रिपाठी ने कहा कि सब समय का फेर होता है। अब फिर समाजवादी सरकार के उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ होने का समय आ गया है। श्री त्रिपाठी जी वहां गीता दर्पण पढ़ रहे थे और उनकी पोती अदिति त्रिपाठी अंग्रेजी किताब पढ़ रही थी। वह पांचवी कक्षा की छात्रा हैं। दादा अपनी पोती को पार्क में घुमाने लाये थे।

त्रिपाठी जी के बराबर की बेंच पर बालागंज, लखनऊ से पार्क घूमने आए मोहम्मद आरिफ अपनी पत्नी श्रीमती फिरदौस के साथ बेठे थे। वहीं एक नौजवान श्यामजी मिश्रा त्रिवेणीनगर, सीतापुर रोड से आए थे।

जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ की गंगा-जमुनी तहजीब का एक नायाब उदाहरण है। यहां सभी धर्म, जाति और विचारों के लोग एकत्र होते है। खुले माहौल में स्वच्छ हवा में सांस लेते हैं। एशिया के इस सबसे बड़े पार्क में भ्रमण करने वालों के पैर थक जाते हैं किन्तु आंखे थकती नहीं। मन भरता नही है। जो भी यहां आता-जाता है एक बार अखिलेश यादव जी को अवश्य याद करता है, उनको धन्यवाद देता है।

यूपी के बजट में दूरगामी दृष्टिकोण की कमी

अशोक कैथल

सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, लखनऊ विवि

उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2020-21 के लिए 5,12,860 करोड़ रुपए के बजट की अगर वर्ष 2019-20 के बजट से तुलना करें तो यह 33,159 करोड़ रुपये अधिक है। इस बजट के आर्थिक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि इस बजट की कुल अनुमानित प्राप्तियां 5,00,558 करोड़ रुपये तथा कुल व्यय 5,12,860.72 करोड़ रुपये अनुमानित है।

इस बजट की प्रमुख अनुमानित प्राप्तियों में वस्तु एवं सेवा कर तथा वैट से अनुमानित राजस्व-91,568 करोड़ रुपये, वाहन कर से 8650 करोड़ रुपये, स्टाम्प एवं पंजीयन से 23197 करोड़ रुपये तथा आबकारी विभाग से 37,500 करोड़ रुपये की प्राप्ति अनुमानित है।

बजट का आर्थिक विश्लेषण करने पर यह दिखता है कि इसमें नये विश्वविद्यालय खोलने, अटल आवासीय विद्यालय के लिए 207 करोड़, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 111 करोड़ समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18363 करोड़ तथा दिव्यांगों को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन के लिए 621 करोड़ जैसी घोषणाएं तो हैं लेकिन ये और बेहतर किये जा सकते थे अगर उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के साथ शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान ले कर आती। इसका लाभ दूरगामी होता जैसे कि नई तकनीक विकास, नई औद्योगिक विधियों, विद्याओं तथा उपकरणों का विकास सम्भव हो पाता जिससे आने वाली पीढ़ी लाभान्वित हो पाती।

इस बजट में 1200 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य के युवाओं के लिए विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं को विकसित करने के लिए तथा युवा उद्यमिता विकास अभियान (युवा) के अंतर्गत प्रत्येक जिले

में 'युवा हब' स्थापित करने की बात की गयी है, कुछ चिह्नित उद्योगों में स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण के दौरान राज्य सरकार के द्वारा 1000 रुपये तथा केन्द्र सरकार के द्वारा 1500 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। सरकार स्वरोजगार को विकसित करने तथा 2500 रुपये प्रतिमाह भत्ते देने का प्रावधान कर रही है, लेकिन इसके साथ अगर उत्तर प्रदेश जैसे जनसंख्या बहुल राज्य में सरकार लघु, मध्यम एवं कुटीर उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित एवं विस्तृत करने का प्रावधान करती तो इसके लाभ दीर्घकालिक होते जैसे कि- उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी तथा अन्य राज्यों की तरफ होने वाला पलायन रोका जा सकता था। सरकार को कृषि सम्बन्धित गतिविधियों, व्यापारिक कृषि, नई कृषि विद्याओं तथा परंपरागत कृषि के स्थान पर अधिक लाभ अर्जित करने वाली कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

इस बजट में सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य 325 रुपए प्रति क्विंटल करने तथा 'मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण बीमा' के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। ये प्रयास निम्नतम हैं इनको और अधिक किये जाने की आवश्यकता है। इसी अगर आधार संरचना की बात की जाये तो बजट में बुंदेलखण्ड, पूर्वांचल क्षेत्र में बिजली, सड़क, जल आपूर्ति विस्तृत करने पर, जेवर हवाई अड्डे, अयोध्या हवाई अड्डे को विकसित करने, कानपुर तथा अन्य शहरों में मेट्रो के विस्तार की बात है। स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए 20,000 करोड़ रुपये, एसजीपीजीआई के लिए 820 करोड़ रुपये तथा कैंसर संस्थान के लिए 187 करोड़ रुपये व पेयजल परियोजना जल जीवन मिशन के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये है, लेकिन सच्चाई यह है कि बजट में सरकार के द्वारा आधार संरचना के लिए कम राशि आवंटित की गयी है।

बुंदेलखण्ड क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों को अगर विकसित करना है तो सड़कों का जाल बिछाना होगा, सड़कों के किनारे स्थित सरकारी जमीनों पर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भवनों का निर्माण कराया जाना चाहिए जिससे सरकार की आय भी बढ़ेगी तथा लोग अपने ही क्षेत्र में रोजगार भी प्राप्त कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही हैं चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, घरेलू क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र हो। इन बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार नवकरणी ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर्य ऊर्जा को विकसित कर सकती है। इसके लिए सरकार सड़कों के दोनों किनारों पर सौर्य ऊर्जा पैनलों को लगाकर ऊर्जा की प्राप्ति कर सकती है। इससे अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति तो होगी ही साथ में अन्य राज्यों से ऊर्जा क्रय करने पर हो रहे व्यय को भी सीमित किया जा सकेगा।

सरकार को हर एक जिला मुख्यालयों में उच्चकृष्ट सुविधाओं से लैस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्रों को स्थापित करने पर जोर देना चाहिए। सरकार जल जीवन मिशन पर जोर दे रही हे, इसके साथ-साथ सरकार को वर्षा जल संरक्षण उपक्रमों को भी हर एक ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में विकसित करने पर बजट में प्रावधान करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश सरकार के इस बजट में महिला सुरक्षा की बात की गयी है, जैसे कि तलाकशुदा महिलाओं को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन, तीन तलाक पीड़िताओं के लिए 1425 करोड़ रुपये का प्रावधान, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था तथा गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए 51 हजार रुपये तक वित्तीय सहायता के प्रावधान की बात की गयी है। जनजातियों के आवास के लिए 370 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं परन्तु इनमें सामाजिक सुरक्षा उपक्रम भी सम्मिलित होते तो और अच्छा हो सकता था जैसे कि निःशुल्क बीमा, निःशुल्क चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, आवासीय सुविधाएं, पोषण युक्त आहार तथा वर्ष भर के लिए रोजगार के अवसरों की उपलब्धता।

(यह लेखक के अपने विचार हैं।)

असंवैधानिक है चौराहों पर यूं पोस्टर लगाना

क़ानूनी पहलू

देवेन्द्र उपाध्याय

एडवोकेट

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध कर रहे लोगों पर लोक तथा निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाकर लोक तथा निजी सम्पत्ति को क्षति की वसूली के लिए सार्वजनिक स्थानों पर उक्त व्यक्तियों के नाम, पता व फोटो के पोस्टर लगाना प्रथम दृष्टया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का पूर्णतया उल्लंघन है। जिसके अनुसार "किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा अन्यथा नहीं।"

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे लोगों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी एवं कुछ व्यक्तियों को जेल में भी निरूद्ध किया गया। जिसके उपरान्त उन लोगों को माननीय न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध आरोप साबित होने तक जमानत पर रिहा किया गया। इसका अर्थ यह निकलता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में उन पर दंगा करने, सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान आदि के आरोप लगाये हैं। जब तक उक्त पर विवेचना के उपरान्त पुलिस आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल न कर दे एवं माननीय न्यायालय द्वारा उन आरोपों पर विचारण के उपरान्त दोषी करार न दिया

जाये, तब तक सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान किसने किया है कोई नहीं बता सकता।

अब यह प्रश्न उठता है कि राज्य सरकार बिना उपरोक्त प्रक्रिया अपनाये किसी व्यक्ति से सार्वजनिक व निजी सम्पत्ति को वसूली कैसे कर सकती है? और जब वसूली ही नहीं कर सकती है तो सार्वजनिक स्थान पर उन व्यक्तियों के नाम, पता व फोटो सहित पोस्टर कैसे लगा सकती है? राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों के नाम, पता व फोटो पोस्टरों द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने के उपरांत उन सभी लोगों को उनकी जान का खतरा बन गया है। उसके उपरांत कोई भी व्यक्ति उन लोगों के घर जाकर उनको जान से मार सकता है, उनको बंधक बना सकता है। अतः नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे लोगों पर लोक तथा निजी सम्पत्ति हानि का आरोप लगाकर लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति की वसूली हेतु सार्वजनिक स्थानों पर उक्त व्यक्तियों के नाम, पता व फोटो के पोस्टर लगाना प्रथम दृष्टया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का पूर्णतया उल्लंघन है एवं समाज में सार्वजनिक रूप से उन सभी का राज्य सरकार द्वारा मानहानि भी की गई हैं । मानहानि की व्यवस्था धारा 499, 500 व 501 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता दी गई है। जिसके अनुसार " जो कोई बोले गये या पढ़े जाने के लिए आरोपित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है तो ऐसे लांछन में ऐसे व्यक्ति की ख्याति को अपहानि की जाये या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति के ख्याति की अपहानि होनी एतस्थि पश्चात अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है।"

जो कोई बोले गये या पढ़े जाने के लिए आरोपित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है तो ऐसे लांछन में ऐसे व्यक्ति की ख्याति को अपहानि की जाये या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति के ख्याति की अपहानि होनी एतस्थि पश्चात अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है।

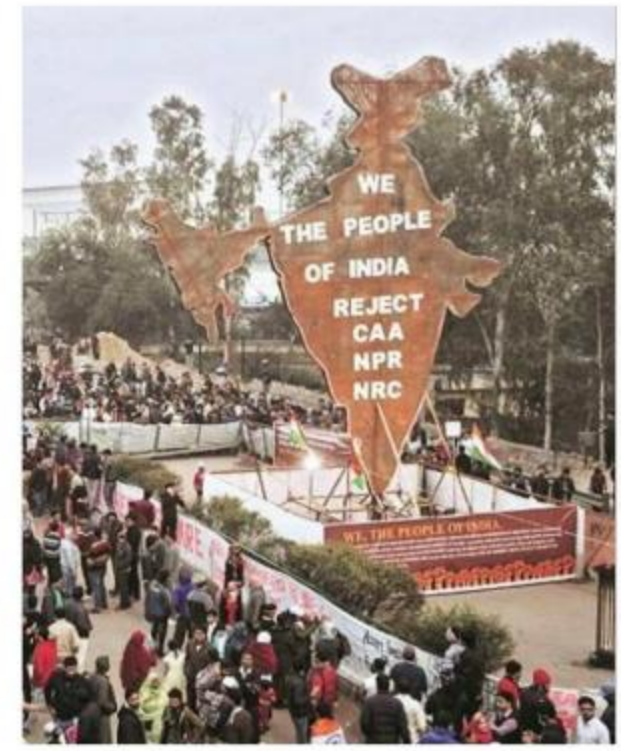

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा " मानक सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब एवं हरियाणा राज्य व अन्य एआईआर 1981 एससी 760" में यह व्यवस्था दी है कि यदि किसी अपराधी, जिस पर कई आपराधिक मुकदमें लगे हैं और उसकी हिस्ट्री शीट खोलनी या बनानी हो तो उक्त अपराधी, की हिस्ट्रीशीट भी जनता के समक्ष में प्रकाशित नहीं की जा सकती।

पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, एआईआर 1997 एससी 568 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि टेलीफोन टेप करना एकान्तता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। अब हम अगर यह माने तो जब कोई किसी की फोन की बाते नहीं सुन सकता है तो राज्य सरकार सार्वजनिक स्थान पर उन व्यक्तियों के नाम, पता व फोटो सहित पोस्टर कैसे लगा सकती है। राज्य सरकार द्वारा उक्त लोगों का सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर लगाना कानून के विरूद्ध किया गया कृत्य है।

फार्म ४

(नियम ८ देखिए)

१	प्रकाशन का स्थान -	समाजवादी बुलेटिन, 19 विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ
२	प्रकाशन अवधि-	मासिक
३	मुद्रक का नाम-	प्रो. रामगोपाल यादव, सदस्य राज्यसभा
	(क्या भारत का नागरिक है)-	भारतीय
	(यदि विदेशी मूल है तो मूल देश)-	X
	पता-	46 ए फ्रेंड्स कालोनी, इटावा
४	प्रकाशक-	प्रो. रामगोपाल यादव
	(क्या भारत का नागरिक है)-	भारतीय
	(यदि विदेशी मूल है तो मूल देश)-	X
	पता-	46 ए फ्रेंड्स कालोनी, इटावा
५	संपादक-	प्रो. रामगोपाल यादव
	(क्या भारत का नागरिक है)-	भारतीय
	(यदि विदेशी मूल है तो मूल देश)-	X
	पता-	46 ए फ्रेंड्स कालोनी, इटावा
६	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के 1% से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।	समाजवादी पार्टी, 19 विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ

मैं प्रो. रामगोपाल यादव एतदद्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार दिए गए विवरण सत्य हैं।

दिनांक- 1 मार्च 2020

प्रकाशक के हस्ताक्षर

प्रो. रामगोपाल यादव

Akhilesh Yadav

@yadavakhilesh

Socialist Leader of India. Chief Minister of UP (2012 - 2017)

Following

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh · Apr 1

जनता में विश्वास जगाने हेतु सरकार को आगे आकर ये बताना चाहिए कि प्रदेश के हर ज़िले में कोरोना की जाँच के कितने किट उपलब्ध हैं, संक्रमण की आशंका वाले लोगों को अलग रखने के लिए कितने आइसोलेशन वार्ड व कोरोना-ग्रसित मरीजों के इलाज के लिए कितने वेंटीलेटर हैं।इससे लोगों का डर कम होगा।

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh · Mar 28

जितने लोगों ने थाली बजाई थी वो लोग आज आगे बढ़कर एक और अच्छा काम करें... आज वही थाली भरकर वो आस-पड़ोस में भटक रहे भूखे लोगों का पेट भरें तो मानवता के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान खिल उठेगी.

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh · Apr 2

If the govt is willing to put aside political differences in these difficult times, Samajwadi Party workers can lend a helping hand using cycles to distribute food to the villages, especially to children who rely heavily on mid-day-meals for their daily nutrition. We are ready!

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh · Apr 3

जनता में विश्वास जगाने के लिए, सरकार से अपेक्षा है कि वो मीडिया में आ रही इन बातों को स्पष्ट करे:

- क्या प्रति 10 लाख केवल 32 लोगों की ही कोरोना जाँच हुई है
- क्या क़िल्लत के समय में भी मेडिकल उपकरणों का निर्यात हुआ है
- क्या केवल मनरेगा व राशन कार्ड धारक को ही राशन मिल रहा है

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh · Mar 27

समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा जी ' बेनी बाबू जी ' का निधन अत्यंत दुःखद! परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh · Mar 26

आज प्रदेश की सड़कों पर जिस प्रकार लाखों लोग भूखे-प्यासे हैं और आपूर्ति के अभाव में जनता त्रस्त है, ऐसे में मुख्यमंत्री जी सपा सरकार के समय भोजन के लिए वितरित किए गये 'समाजवादी राहत पैकेट' को बाँटने का निर्देश ज़िलाधिकारियों को जारी करें जिनके नियम भी बने हैं. चाहें तो नाम बदल दें

साफ़ और बेबाक

पंजीकृत डाक पंजीकरण संख्या LW/NP-300/2018-2020

नर की सेवा
नारायण की सेवा

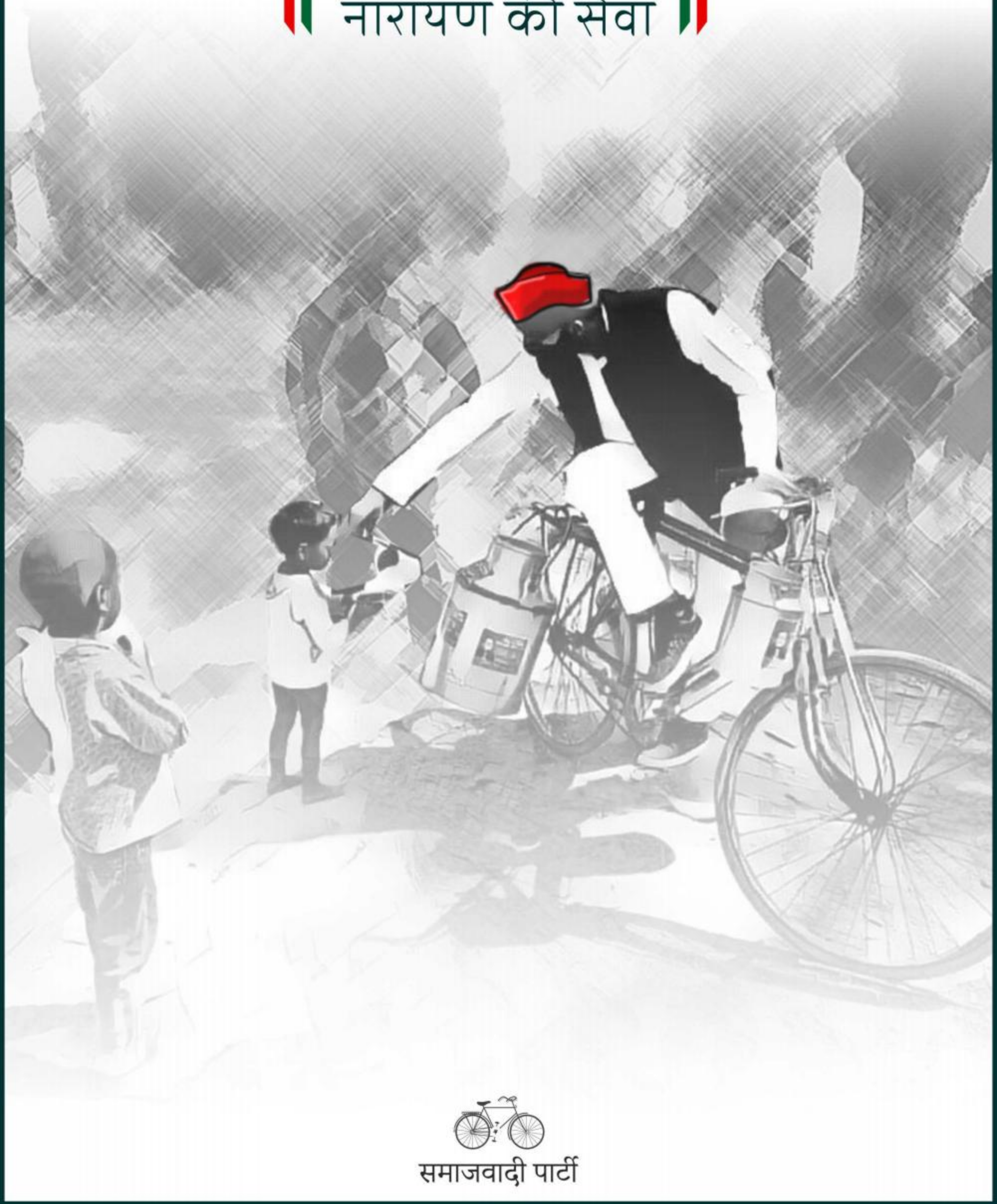

समाजवादी पार्टी

www.samajwadiparty.in